Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग
0788-4030383, 3293199
भगवान के वस्त्र, श्रृंगार मूर्तियां एवं समस्त पूजन सामग्री संगमरमर व पीतल की मूर्तियां राशि रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...
रायपुर, दुर्ग एवं जगदलपुर से प्रकाशित

समय दर्शन

ESTD : Since 2011
संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर
निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

श्री
दुर्ग शहर में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 01, अंक 18 | पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रूपये | जगदलपुर, बुधवार 25 मार्च 2026 | www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

असम के एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार

डिब्रूगढ। वायुसेना और राजस्थान इंटेलिजेंस की टीम ने असम के वायुसेना अड्डे पर तैनात एक कर्मचारी को पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुमित कुमार (36) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के लाहुरपार का निवासी है और एयरफोर्स स्टेशन में एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के पद पर कार्यरत है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (खुफिया विभाग) प्रफुल्ल कुमार के अनुसार सुमित कुमार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भारतीय वायुसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां एकत्रित करता था और उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचाता था। जांच में सामने आया है कि वह वर्ष 2023 से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में था और पैसों के बदले गोपनीय सूचनाएं साझा कर रहा था। इस मामले की शुरुआत जनवरी 2026 में राजस्थान के जैसलमेर निवासी झबराराम की गिरफ्तारी से हुई थी। उससे पूछताछ के दौरान सुमित कुमार का नाम सामने आया।

हल्की बारिश के साथ पूरे सप्ताह छाए रहेंगे बादल

नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार आज यानी 23 मार्च को एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पूरे सप्ताह आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 23 मार्च को अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आम तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी वाला रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 24 मार्च को तापमान 31/15 डिग्री, 25 मार्च को 32/15 डिग्री, 26 मार्च को 33/17 डिग्री, 27 मार्च को 33/17 डिग्री और 28 मार्च को 33/17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

जौनपुर में गोतस्कर और पुलिस में मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार

जौनपुर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25 हजार रुपए का इनामी गोतस्कर आरिफ घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ प्रतिमा वर्मा ने बताया कि इस कार्रवाई को मीरगंज और मछलीशहर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरिफ के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू में कर लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त होगा

नई दिल्ली/ एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सांविधानिक आदेश, 1950 में साफ कहा गया है कि खंड-3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म के बावजूद, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति के मामले में दिया गया, जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पेस्टर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसने कुछ लोगों के खिलाफ एससी-एसटी (अत्याचार रोकथाम) कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने एससी-एसटी कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित ईसाई धर्म अपना चुका है। 30 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति एससी-एसटी कानून के प्रावधानों का लाभ लेने का पात्र नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज धाराओं को खत्म करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा 'इस मामले में ये अहम नहीं है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म से अपने मूल धर्म में धर्मांतरित हो गया है या उसे उसके मूल समुदाय द्वारा स्वीकार किया गया है या नहीं। बल्कि सबूतों से ये सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ईसाई धर्म का पालन करता है और एक दशक से अधिक समय से बतौर पादरी काम कर रहा है। वह गांव के घरों में नियमित तौर पर रविवार की प्रार्थनाएं आयोजित करता है। इस तथ्यों से इस बात में कोई शक नहीं है कि घटना के समय वह ईसाई बना रहा।' अदालत ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। यानी किसी अन्य धर्म को अपनाने पर स्ष्ट का दर्जा स्वत: समाप्त हो जाता सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने से स्ष्ट का दर्जा स्वत: समाप्त हो जाता है।

अब भारतीय सेना की महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन शॉर्ट सर्विस मामले में अदालत का अहम फैसला

भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेवा देने वाली महिला अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने सेना में महिलाओं के खिलाफहोने वाले प्रणालीगत भेदभाव को स्वीकार करते हुए अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 142) का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने उन महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया जिन्हें स्थायी कमीशन से वंचित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिन महिला अधिकारियों ने अपनी सेवा से हटाए जाने को लेकर अदालत में चुनौती दी थी, उन्हें 20 साल की सेवा के बराबर पेंशन पाने का हकदार माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफकिया कि सेना में महिलाओं के खिलाफप्रणालीगत भेदभाव की वजह से उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सेना में केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं हो सकता। जस्टिस ने साफकिया कि पुरुष अधिकारी यह उम्मीद नहीं कर सकते कि भविष्य के सभी खाली पद केवल उनके लिए ही होंगे। कोर्ट के अनुसार, अवसरों की कमी और गलत तरीके से अयोग्य ठहराए जाने के कारण महिला अधिकारियों की योग्यता और उनके करियर की प्रगति पर बुरा असर पड़ा है।

लैंड फॉर जॉब मामले

लालू प्रसाद यादव की फिर बढ़ी मुश्किलें याचिका हुई खारिज....

नई दिल्ली/ एजेंसी

लैंड फॉर जॉब मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई के मामले को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, लालू प्रसाद यादव ने अदालत में याचिका दायर कर यह दलील दी थी कि सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल नहीं की है इसलिए पूरे मामले को निरस्त किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है, अदालत की

टिप्पणी में स्पष्ट किया गया कि प्रस्तुत दलीलें मामले को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया, जिससे उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। लैंड फॉर जॉब मामला उन आरोपों से संबंधित है कि 2004 और 2009 के बीच रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रेलवे में नियुक्तियां की, जिसके बदले में उनके परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी संस्थाओं को जमीन के टुकड़े हस्तांतरित किए गए। सीबीआई के अनुसार, उम्मीदवारों या उनके रिश्तेदारों ने कथित तौर पर बाजार दर से कम कीमतों पर जमीन हस्तांतरित की, जो विभिन्न रेलवे जोन में नौकरियों के बदले में दी गई थी। हालांकि, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने इन आरोपों से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को इसके गुण-दोष के आधार पर लड़ेंगे।

आतंकवाद से जुड़े मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कश्मीर में सोमवार को कई जगहों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आतंकवाद से जुड़े एक मामले को लेकर की गयी है। जिसमें कुपवाड़ा और कुलगाम में तलाशी अभियान चलाया गया है। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ कुलगाम जिले में तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े एक मामले के सिलसिले में कई जगहों पर छापेमारी की।

बजट में महिला सम्मान योजना का ऐलान

दिल्ली में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने आज अपना वार्षिक बजट पेश किया। बजट में अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 800 करोड़ रुपये और दिल्ली जल बोर्ड को 9000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इससे पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया गया, जिसके मुताबिक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब 2.5 गुना यानी 5.1 लाख रुपये रहने का अनुमान है। सर्वे में यह भी कहा गया कि दिल्ली का जीएसडीपी 9.4 प्रतिशत बढ़कर 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। राजधानी की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 86

प्रतिशतसे ज्यादा है। 1 लाख करोड़ रुपये के बजट में परिवहन को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है। इसमें मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को प्रमुख उपलब्धियों के तौर पर पेश किया गया।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला जोरदार हमला

भारत की विदेश नीति मोदी की निजी पॉलिसी-राहुल...

नई दिल्ली/ एजेंसी

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारत की विदेश नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी पॉलिसी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि स्ट्रकच्रल गलती हुई है। इसके अलावा राहुल ने पीएम मोदी पर अमेरिका और इजरायल की बात सुनने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी गलती को ठीक कर ही नहीं सकते बल्कि वह तो अमेरिका जो कहेगा, इजरायल जो कहेगा वह करेंगे।

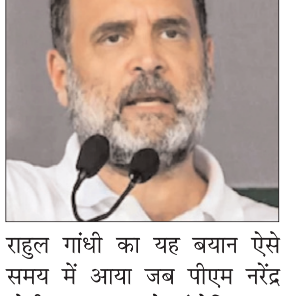

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया जब पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा को संबोधित कर रहे थे। कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा को संबोधित किया था। जहां उन्होंने बताया था कि भारत लगातार युद्ध के प्रभावित देशों में फंसे भारतीयों को निकाल रहा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह साफ कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। अब यह एक यूनिवर्सल मज़ाक जैसा हो गया है, अगर हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं तो फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, हमारी क्या पोजीशन है? कोई पोजीशन नहीं है लोगों को इसका नुकसान होगा। अभी केवल शुरुआत हुई है। अभी सभी चीजों में परेशानी होगी, अमेरिका और इजराइल जो कहेगा प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे।

2 पत्नियां-18 बच्चे फिर भी किया इश्क, प्रेमिका ने घर बुलाकर उतारा मौत के घाट

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पूर्व प्रधान मुस्तका गुलशन उर्फ मुन्ना की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। उनका शव बोरे में भरकर नहर में फेंका गया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक की कथित प्रेमिका सुमन को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। यह घटना मांधाता कोतवाली क्षेत्र के मिश्रपुर गांव की है। 18 मार्च को मुन्ना अचानक लापता हो गए थे। बाद में सुमेरपुर गांव के पास नहर में एक संदिग्ध बोरा मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।

हरीश राणा ने दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस

भारत में इच्छा मृत्यु पाने वाले पहले व्यक्ति का हुआ निधन...

नई दिल्ली/ एजेंसी

भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का 13 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद एम्स दिल्ली में निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों की निगरानी में उनका न्यूट्रिशनल सपोर्ट धीरे-धीरे बंद कर दिया गया था। साथ ही उन्हें दर्द से राहत देने वाली दवाएं दी जा रही थीं जिससे उनकी अंतिम अवस्था बिना कष्ट के गुजर सके। लंबे समय से कोमा में रहने के कारण हरीश की हालत बेहद

गंभीर बनी हुई थी। मेडिकल टीम ने सभी कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उनकी देखभाल की और यह सुनिश्चित किया कि उनकी अंतिम बिना किसी दर्द के पूरी हो सके। दरअसल, हरीश राणा की लगातार बिगड़ती हालत और सुधार की कोई संभावना न होने पर उनके परिवार ने कानूनी रास्ता अपनाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया, यानी जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दे दी। अदालत ने माना कि गरिमा के साथ मृत्यु भी जीवन के अधिकार का अहम हिस्सा है। यह ऐतिहासिक फैसला भारत के चिकित्सा और कानूनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन गया, जिसने असाध्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए सम्मानजनक और शांतिपूर्ण विदाई का रास्ता खोला।

ईरान युद्ध जारी रहा तो गंभीर दुष्परिणाम होंगे

आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेगा-पीएम मोदी

नई दिल्ली/ एजेंसी

संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के भारत पर प्रभाव और पश्चिम एशिया के हालात पर राज्यसभा में 21 मिनट बोले। पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध जारी रहा तो इसके गंभीर दुष्परिणाम होंगे। आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करने होगा। एक दिन पहले पीएम ने लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के साथ संपर्क में हैं। हमने हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी ईरान से बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट अस्वीकार्य है। साथ ही भारत ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में हमारे जहाज और भारतीय क्रू फंसा हुआ है। ये चिंताजनक है। हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। गैस-तेल, फर्टिलाइजर्स जैसे जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर बात की है। कमर्शियल जहाज पर हमला अस्वीकर है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का रास्ता सुझाया है। किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। पीएम ने कहा कि भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। जंग शुरू होने से अबतक 3 लाख 75 हजार से ज्यादा भारतीय देश लौट चुके हैं। ईरान से एक जहजार से अधिक भारतीय लौटे हैं। इनमें 700 से

अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीय की सुरक्षा का भरोसा दिया है। हमलों के कारण कुछ भारतीयों की मौत हुई है। यह दुखद है। उनके परिवार को मदद दी जा रही है। जो घायल हैं उन्हें इलाज दी जा रही है। पीएम ने कहा कि पहले भारत में 27 देशों से एनर्जी इम्पोर्ट किया जाता था। आज 41 देशों से एनर्जी इम्पोर्ट किया जाता है। हमने कच्चे तेल के भंडार को भी प्राथमिकता दी है। बीते 10 साल में रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। देश को भरोसा देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल की निरंतर सप्लाई की व्यवस्था है। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी जोर दे रही है। एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ाने का काम जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में आने वाली दिक्कतों का आकलन करता है। कोरोना के समय में अलग-अलग सेक्टर से निपटने के लिए अफसरों के एम्पॉवर्ड ग्रुप बने थे, वैसे ही अभी 7 एम्पावर्ड ग्रुप बने हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले बुआई के सीजन में किसानों को खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की सप्लाई के लिए तैयारी की है। किसानों को आश्वस्त करूंगा कि सरकार हर चुनौती के समाधान के लिए उनके साथ खड़ी है। ये राज्यों का सदन है। आने वाले समय में संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें सफलता के लिए राज्यों का सहयोग जरूरी है।

सुरक्षित वतन लौटे 3.75 लाख भारतीय

खाड़ी देशों में रहने वाले लगभग एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। प्रधानमंत्री ने सदन को कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी दिए। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 3.75 लाख भारतीय सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। अकेले ईरान से 1,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया है, जिनमें 700 से ज्यादा मेडिकल छात्र शामिल हैं। होर्मुज स्ट्रेट में फंसे जहाजों में बड़ी संख्या में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सरकार गंभीर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा से समाधान के लिए 'संवाद' का रास्ता सुझाया है क्योंकि मानवता के हक में युद्ध कभी विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि संकट शुरू होने के बाद से वे पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के नेतृत्व के साथ दो दौर की वार्ता कर चुके हैं।

संक्षिप्त समाचार

विश्व क्षय रोग दिवस पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ

पाटन (समय दर्शन)। दिनांक 24 मार्च 2026 को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष श्री निक्की भाले, उपाध्यक्ष श्रीमती निशा सोनी एवं सभापति श्री केवल देवांगन द्वारा किया गया। इस अवसर पर बीएमओ पाटन डॉ. बी. कथौतिया, बीपीएम श्रीमती पूनम साहू, एसटीएस इंदु अमृत, श्री रुपेंद्र देशमुख, रेडियोग्राफर श्री जितेंद्र सहित समस्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान टीबी उन्मूलन के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही, टीबी की शीघ्र पहचान एवं जांच को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हैंड-हेल्ड एक्स-रे मशीन की शुरुआत भी की गई, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से जांच की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने निक्षय मित्र बनने का संकल्प लिया तथा टीबी मरीजों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु पोषण आहार (फूड बास्केट) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

जनसमुदाय को बताया गया कि टीबी एक पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते समय पर जांच एवं नियमित उपचार किया जाए। साथ ही, खांसी 2 सप्ताह से अधिक रहने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की गई। कार्यक्रम में सभी उपस्थितजनों ने टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया तथा समाज से इस बीमारी को समाप्त करने में सहयोग देने का आह्वान किया।

स्टेशनपारा वार्ड में लगा सबमर्सिबल पंप और पानी टंकी

राजनांदगांव। गर्मी की वजह से पानी की समस्या से परेशान स्टेशनपारा वार्ड नंबर 11 के निवासियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है। वार्डवासियों और राहगीरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, वार्ड पार्षद छोटेलाल रामटेके ने पार्षद निधि से वार्ड में सबमर्सिबल पंप और पानी टंकी लगवाया।

इस अवसर पर कांग्रेस नेता आसिफ अली भी उपस्थित रहे। पंप और टंकी के उद्घाटन के दौरान स्टेशनपारा वार्ड की महिलाओं सहित अन्य वार्डवासी भी मौजूद थे। वार्डवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए बताया कि गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत काफी हद तक कम होगी और अब उन्हें रोजमर्रा के कामकाज में सुविधा होगी। उक्त जानकारी हितेश गोन्नाड़े ने दी।

स्कोडा ऑटो इंडिया ने ईज़ी टू लव नईकुशाक के लॉन्च के साथ वैल्यू, परफॉर्मेंस और सेफ्टी कोनए सिरे से परिभाषित किया है

स्कोडा ऑटो इंडिया ने रिफ्रेश्ड और अपग्रेडेड नई कुशाक की कीमतों औरकस्टमर डिलीवरी शुरू होने की घोषणा कर दी है। इस साल जनवरी में लॉन्चहुई नई कुशाक, वैल्यू, सेफ्टी, ड्राइविंग डायनामिक्स के मामले में सबसे आगेहै और पूरी रेंज में यूरोपियन टेक्नोलॉजी को सबके लिए लाने की ब्रांड कीस्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाती है। सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी जैसे बिल्कुल नयाएट-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, रियर सीट मसाजर, और कईनए फीचर्स के साथ-साथ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ, नई कुशाक 1.0 TSI और नई कुशाक 1.5 TSI दोनों ही स्कोडा ऑटो इंडिया की यूरोपियनइंजीनियरिंग और 5-स्टार सेफ्टी को भारतीय सड़कों पर ज़्यादा आसानी सेचलने वाली बनाने की स्ट्रैटेजी को फॉलो करती हैं। नई कुशाक पांच ट्रिम्स मेंउपलब्ध है: क्लासिक+, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो, जोमैनुअल और रियल ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजनका ऑप्शन देती है।

प्रदेश स्तरीय रानी अवंती बाई लोधी बलिदान दिवस का आयोजन

पाटन ब्लॉक से भी समाज के लोग कार्यक्रम में हुए शामिल

गाड़ाडीह (समय दर्शन)। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर ग्राम सेमरिया में प्रदेश स्तरीय भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने की।अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा , अभिषेक सिंह पूर्व सांसद एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में समाज के अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में स्वागत भाषण संतोष कौशिक ने प्रस्तुत किया। समाज की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के त्याग, बलिदान एवं वीरता पर प्रकाश डालते हुए समाज के गौरवशाली इतिहास को रेखांकित किया तथा प्रदेशभर में समाज के विकास हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। प्रमुख मांगों में कबीरधाम जिले में 50 डिसमिल भूमि एवं 50 लाख रुपये की स्वीकृति, नया रायपुर में एक एकड़ भूमि एक रुपये के दर पर प्रदान करने, रायपुर जिला अस्पताल का नामकरण वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर करने तथा वीरांगना अवंती बाई लोधी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग शामिल रही। इसके अतिरिक्त ग्राम गोछिया (जिला कबीरधाम) में नवीन महाविद्यालय का नाम वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर स्वीकृत करने, ग्राम सेमरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने, ग्राम मुसरा (तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव) में बजट में स्वीकृत नवीन महाविद्यालय का नामकरण वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी के नाम पर करने की मांग रखी गई। साथ ही ग्राम सेमरिया में यज्ञशाला स्ट्रक्चर निर्माण हेतु 20 लाख रुपये की मांग, तथा वीरांगना अवंती बाई लोधी महाविद्यालय रामाटोला को पुनर्जीवित करने के लिए राजनीतिक विज्ञान विषय में एक पद सृजन एवं वार्षिक अनुदान पुनः प्रारंभ करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ने अपने संबोधन में लोधी समाज के सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए समाज को बधाई दी तथा उनके गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोधी समाज को संगठित, अनुशासित एवं नशामुक्त समाज बताते हुए इसे देश का अग्रणी समाज कहा। वहीं विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने लोधी समाज के लोगों की मेहनत, ईमानदारी एवं समर्पण की प्रशंसा की। सभी अतिथियों ने एक स्वर में लोधी समाज की मांगों का समर्थन किया। कार्यक्रम में गिरवर जंघेल पूर्व विधायक, कोमल जंघेल पूर्व विधायक, भारत वर्मा पूर्व प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, कमलेश्वर वर्मा, डां अशोक वर्मा जी प्रदेश सलाहकार ,जीवन कौशिक संगठन मंत्री ,विष्णु लोधी कोषाध्यक्ष, , विमल पटेल अंकेक्षक, सुरेश सिंगौर युवा प्रदेश अध्यक्ष दशमत जंघेल जगदीश वर्मा, जागेश्वरी वर्मा पीला राम कौशिक राष्ट्रीय संगठन मंत्री, रामफल कौशिक आजू कौशिक प्रदेश प्रचार सचिव अधीन जघेल, भुपेंद्र चंदेल , राजेन्द्र चंद्रवंशी जिला अध्यक्ष भाजपा कैलाश चंद्रवंशी जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ज्योति जंघेल, लक्ष्मी जघेल अदिति कश्यप, उषा कौशिक जिला अध्यक्षगण बनऊ वर्मा, गोवेंद पटेल, उत्तम चंद जंघेल जमुना प्रसाद वर्मा तेज शंकर जंघेल संजू कौशिक जिला महासचिव राजेश कौशिक राजेश कौशिक जनपद सदस्य राजेश कौशिक संगठन मंत्री दीपक जघेल महासचिव मनहरण कौशिक पूर्व पालिकाध्यक्ष, रुपेश कौशिक युवा जिला अध्यक्ष एवं जनपद सरपंच सभी जिला के सभी सर्किल अध्यक्ष गण, एवं पदाधिकारी गण सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज की एकता एवं विकास पर जोर दिया।

पंचमी पर अमित जोगी ने मां बम्लेश्वरी दरबार में टेका मत्था, प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना

डोंगरगढ़ (समय दर्शन)। चैत्र नवरात्र की पंचमी के पावन अवसर पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने डोंगरगढ़ स्थित ऐतिहासिक मां बम्लेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली, शांति एवं समृद्धि की कामना की। जोगी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के साथ जिला उपाध्यक्ष जाहिर खान, निलेश चौहान, ईश्वर उपाध्याय, अजीत जोगी युवा मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसूल आलम मुख्य रूप से डोंगरगढ़ पहुंचे। श्री जोगी के आगमन पर आगमन पर पार्टी के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रवेश द्वार पर भव्य स्वागत किया। पटाखों और फूल-मालाओं के साथ हुए इस स्वागत से श्री जोगी भावुक हो उठे। इसके पश्चात वे जयघोष के बीच पैदल चलते हुए रोप-वे तक पहुंचे और मां के दरबार में मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर श्री जोगी ने कहा कि मां बम्लेश्वरी मंदिर का उनके जीवन में विशेष महत्व रहा है। स्वर्गीय अजीत जोगी ने वर्ष 1997 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु अपनी ऐतिहासिक छत्तीसगढ़ यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी। माता के आशीर्वाद से ही वर्ष 2001 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश का ऐतिहासिक महिला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने अध्यक्षता की थी। इसी दौरान मितानिन योजना की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर पूरे देश में आशा कार्यकर्ता व्यवस्था का आधार बनी।

मंदिर परिसर में सैकड़ों शुभचिंतकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। दर्शन उपरांत उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर ट्रस्ट द्वारा गरीबों एवं रोगियों की सेवा के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री जोगी ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा से मुकाबले के लिए विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टी के विलय का प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व ही कांग्रेस हाईकमान को सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। साय सरकार को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने 26 महीनों मोदी की तीन गारंटियों को पूरा किया है, जिसमें शराब बिक्री, अडानी की एंट्री और अफीम की खेती जैसे मुद्दों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ योजनाओं के माध्यम से केवल चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है।

श्री जोगी ने कहा कि सरकार एक ओर शराबबंदी की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश को शराब और नशे की ओर धकेला जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण विधेयक को लाने से पहले व्यापक चर्चा और परामर्श होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

शक्तिधाम महाकाली मंदिर में पंचमी पर मां महाकाली का भव्य श्रृंगार, भक्तों की उमड़ी भीड़

राजनांदगांव। शहर के वार्ड नंबर 1, बाबुटोला स्थित शक्तिधाम महाकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान मंदिर में सात दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन भी किया गया है। यज्ञ शाला का परिक्रमा करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

नवरात्र के पंचमी के शुभ अवसर पर मां महाकाली का विशेष मनोरम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर में महाआरती के बाद जस जगराता का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त देर रात तक भजनों में झूमते रहे।

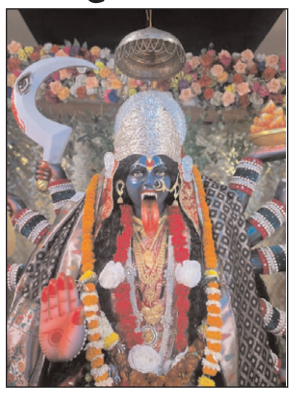

मंदिर के प्रमुख गुरुदेव श्री हरीश यादव ने बताया कि इस वर्ष नवरात्र महोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। पंचमी के दिन भीड़ आम दिनों की तुलना में अधिक रही। सात दिवसीय महालक्ष्मी महायज्ञ में दूर-दूर से श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और उनकी आस्था देखने लायक है।

मंदिर समिति के अध्यक्ष अखिलेश बंजारा ने बताया कि आगामी अष्टमी तिथि को सर्व व्याधि निवारण हेतु उड्डीस तंत्र के तहत 21 साधकों द्वारा अभिमंत्रित धूप का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही निःसंतान दंपत्तियों को संतान प्राप्ति के लिए माता की अर्जी, श्रीफल और अभिमंत्रित औषधि भी मुफ्त दी जाएगी। अभिमंत्रित धूप और औषधि के लिए नामांकन 25 मार्च की रात 8 बजे तक अनिवार्य है।

शक्तिधाम महाकाली मंदिर में नवरात्र के दौरान भक्तों का उत्साह और आस्था देखते ही बन रही है। पंचमी के दिन मां महाकाली के भव्य श्रृंगार और भजन संध्या ने भक्तों के दिलों को भक्तिमय कर दिया।

मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का मिल रहा लाभ, पाटन डिवीजन में लग रहा शिविर

पाटन (समय दर्शन)। पाटन विद्युत वितरण केंद्र में मुख्यमंत्री बिजली बिल योजना के तहत शिविर लगाया गया। जिसमें अब तक 16 सक्रिय उपभोक्ता ने पंजीयन कराया। जिसमें 153906 रुपए जमा की गई। और इन उपभोक्ताओं समाधान योजना के तहत 81526 रुपए की छूट दी है। उसी तरफ असक्रिय उपभोक्ताओं ने 74828 रुपए जमा किए। जिसमें इन उपभोक्ताओं को 106922 रुपए का छूट का लाभ मिला। शिविर में मुख्य कार्यपालन अभियंता बी पी दीपक, कनिष्ठ अभियंता राकेश कुमार साहू ने उपभोक्ताओं को इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी दी। इस दौरान कार्यालय के स्टाफके अलावा उपभोक्ता की मौजदगी रही। जानकारी के मुताबिक पाटन डिवीजन में 235 सक्रिय उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जिनमें से अभी तक 162 उपभोक्ता ने रजिस्ट्रेशन करवा कर योजना का लाभ ले रहे है। यह शिविर अलग अलग वितरण केंद्र में 30 मार्च तक जारी रहेगा। पाटन डिवीजन के द्वारा इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिससे कि पात्र उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।

भारत की जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 25 में कुल लाभ के रूप में 6.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया, घरेलू वित्तीय सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ बनकर उभरीं - इंश्योरेंस अवेयरनेस कमिटी (आईएसी-लाइफ)

मुंबई: भारत का जीवन बीमा क्षेत्र परिवारों की सुरक्षा और दीर्घकालिक वित्तीय नियोजन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नवीनतम आईआरडीएआई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, जीवन बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल लाभ के रूप में 6.30 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह आंकड़ा उस समर्थन के स्तर का प्रमाण है जो जीवन बीमा उद्योग भारतीय परिवारों को सुरक्षा से लेकर सेवानिवृत्ति और धन सृजन तक जीवन के विभिन्न चरणों में प्रदान करता है। इंश्योरेंस अवेयरनेस कमिटी (आईएसी-लाइफ) के चेयरपर्सन कमलेश राव ने जीवन बीमाकर्ताओं के व्यावसायिक दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा, भारत की जीवन बीमा कंपनियों का काम करने का तरीका—जैसा कि उनकी निरंतरता, भुगतान और वित्तीय मजबूती के आंकड़ों से पता चलता है—यह साबित करता है कि जीवन बीमा परिवार के लिए एक 'पैसे के गुल्लक' की तरह है। यह ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसा भी देता है और लंबे समय के लिए सुरक्षा भी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुल भुगतान का 92 प्रतिशत हिस्सा 'लिविंग बेनिफिट्स' (यानी पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर मिलने वाला पैसा) के रूप में दिया गया है। इससे पता चलता है कि यह उद्योग सिर्फ मौत के बाद सुरक्षा देने वाला साधन नहीं है, बल्कि एक भरोसेमंद साथी है जो परिवारों की आर्थिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद करता है।

मध्यप्रदेश ने अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी लीग सब जूनियर बालिका वर्ग का खिताब अपने नाम किया, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रही

राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में सांई सेंटर व हॉकी इंडियाए के द्वारा संचालित व छत्तीसगढ़ हॉकी के द्वारा आयोजित अस्मिता हॉकी वेस्ट जोन लीग 2025-26 के फायनल मुकाबले में मध्यप्रदेश ने मेजबान छत्तीसगढ़ को 5-1 गोल से पराजित करते हुए स्वर्ण पदक के साथ विजेता होने का गौरव हासिल किया। मेजबान छत्तीसगढ़ रजत पदक के साथ उपविजेता व तीसरे स्थान पर हॉकी महाराष्ट्र ने कॉस्य पदक जीता।

प्रतियोगिता का समापन व पुरूस्कार वितरण समारोह सुश्री भारती गौते (वरिष्ठ शिक्षाविद् तथा प्रिंसिपल, एनपीएस, पेंड्री) के मुख्य आथित्य, श्रीमती अमृता मोहन सिन्हा पार्षद, श्रीमती रेखा पदम विक्रम अवॉर्डी, अंतर्राष्ट्रीय व्हालीबाल खिलाड़ी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर फिरोज अंसारी अध्यक्ष छत्तीसगढ हॉकी, विद्याविलाश श्रीवास्तव वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी, शिव नारायण धकेता सचिव जिला हॉकी संघ, मृणाल चौबे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाडी, भूषण साव, नीलमचंद जैन, छोटे लाल रामटेके पार्षद, चंदन भारद्वाज एवं अभिमन्यु मिश्रा आदि विशेष रूप से उपस्थित थे।

अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि सुश्री गौते ने अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी लीग सब जूनियर बालिका वर्ग का पुरूस्कार वितरण में शामिल होने के लिए आयोजन समिति का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज हमारे प्रदेश की बेटियां भारत में प्रतिनिधित्व कर रही है, वह निश्चित रूप से गौरव की बात है। इस प्रकार के आयोजन करने से प्रदेश के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकलने का मौका मिलता है। मैं देखते आ रही हूं छत्तीसगढ़ हाकी लगातार हॉकी को बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रही है। इस प्रकार के आयोजन और प्रयास से राजनांदगांव के खिलाड़ी निखर के सामने आ रहे है। आज की विजेता और उप विजेता टीम को बधाई देते हुए सुश्री गौते ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

छत्तीसगढ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने अपने स्वागत भाषण में बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण, हॉकी इंडिया एवं छत्तीसगढ़ हॉकी के संयुक्त तत्वाधान में महिला हॉकी खेल का बढ़ावा देने के उद्देश्य से अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत सरकार एवं एवं हाकी इंडिया की इस पहल से खिलाड़ियों को उचित मंच प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि अस्मिता वेस्ट जोन हाकी की लीग का आयोजन दिनांक 20 मार्च से 24 मार्च तक स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय हाकी स्टेडियम में किया गया, इसमें जोन से संबंधित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित मेजबान छत्तीसगढ़ की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम चार स्थान तक आने वाली टीमों को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 180000 (मध्य प्रदेश), द्वितीय पुरस्कार 144000 (छत्तीसगढ़), तीसरा (महाराष्ट्र) और चौथा पुरस्कार (राजस्थान) को 90000 रुपये का चेक उपस्थित अतिथियों द्वारा प्रदान किया गया।

आज मध्यप्रदेश और मेजबान छत्तीसगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें मध्यप्रदेश ने छत्तीसगढ़ को 5-1 गोल से पराजित किया। पहले मटर तक मैच बहुत ही रोमांचकारी रहा। मैच के 18वें मिनट में मेजबान छत्तीसगढ़ की ओर से मनप्रीत कौर ने गोल करते हुए 1-0 गोल की बढ़त बनाई थी, जो ज्यादा समय तक नहीं रही। मैच के 23वें मिनट में मध्यप्रदेश की शालिनी सिंग ने गोल कर 1-1 की बराबरी पर ला दिया, इसके बाद मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 25वें मिनट में रूली बाल्मीकि ने 34वें मिनट में सुदीप्त किंडो ने 40वें और 41वें मिनट में नौशीन नाज ने गोल करके अस्मिता वेस्ट जोन हॉकी लीग का खिताब अपने नाम किया।

आज के मैच में प्रिया दुबे, अनामिका शर्मा, राजवीर कौर, कुलदीप कौर, खुशबू सिसोदिया, अमृता सेन, पिंकी नायक, ईशानी पटेल ने निर्णायक व तकनीकी अधिकारी की भूमिका निभाई, वहीं वंदन रघुवंशी टेक्निकल डेलीगेट के रूप में उपस्थित थीं।

समापन समारोह में प्रमुख रूप से सुश्री आशा थामस, प्रिंस भाटिया, अजय झा, किशोर धीवर, शब्बीर खान, चंदन भारद्वाज, तीरथ गिरी गोस्वामी, शकील अहमद, दिग्विजय श्रीवास्तव, शिवा चौबे, दिलीप रावत, योगेश द्विवेदी, सचिन खोब्रागढ़े, अभिनव मिश्रा, हारून खान, खुशाल यादव, सुखदेव निर्मलकर, कार्तिक यादव, तौफीक अहमद, कृष्णा यादव आदि उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

24 घंटे में उठाईगिरी का खुलासा, महिला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। जिले में पुलिस ने साप्ताहिक बाजार में हुई बड़ी चोरी की घटना का महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 12 लाख 64 हजार 50 रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। पेंड्रा के ग्राम बस्ती स्थित साप्ताहिक बाजार में हुई थी। प्रार्थी विनय कुमार सोनी ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि दुकान लगाते समय किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके जेवरों से भरा बैग चोरी कर लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी ने तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कराई। जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अड़भार क्षेत्र में किराए के मकान में रह रही चूड़ी बेचने वाली महिला आशिया शिकारी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में महिला ने चोरी की वारदात कबूल करते हुए बताया कि उसने अपने भतीजे राजेंद्र शिकारी और भांजे अमर शिकारी के साथ मिलकर योजना बनाई थी। तीनों ने बाजार में मौका देखकर बैग चोरी किया और मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 35 ग्राम सोना और 6.550 किलोग्राम चांदी बरामद की है।

पति-पत्नी पर कहर बनकर झूम पड़े मधुमक्खियों का झुंड, एक की मौत

रायपुर। जिले में मधुमक्खियों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। महुआ बीनने जंगल गए दंपति पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरा मामला डौंडी थाना क्षेत्र के गोटूलमुड़ा गांव का है। जानकारी के अनुसार, 65 वर्षीय चम्पूलाल गोयल अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ जंगल में महुआ बीनने गए थे। इसी दौरान मधुमक्खियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। किसी तरह पत्नी सुमित्रा ने अपनी जान बचाई, लेकिन चम्पूलाल गोयल की मौके पर ही मौत हो गई। घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

मां और बेटी की सड़क हादसे में मौत, बोलेरो ने रौंदा

रायपुर। जिले के नरहरपुर मार्ग पर गुरुवार शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। जिस घर में कुछ ही दिनों बाद शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब शोक का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि परिवार का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा जुनवानी चौक के आगे चनार मोड़ के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार ग्राम बनसागर निवासी विकास शोरी अपनी भाभी शिवकुमारी शोरी और भतीजी प्रीति शोरी के साथ बाइक से कांकेर जा रहे थे। शाम करीब 7 बजे कांकेर की ओर से आ रही बोलेरो ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय गोंडवाना आदर्श सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल

आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार-मुख्यमंत्री

- कसडोल में कंवर समाज सामुदयिक भवन तथा पलारी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50-50 लाख रुपए की घोषणा

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम ओड़ान में बावनगढ़ आदिवासी ध्रुव गोंड़ समाज तुरतुरिया माता महासभा लवन के तत्वावधान में आयोजित गोंड़वाना आदर्श सामूहिक विवाह समारोह मे शामिल हुए। इस मौके पर श्री साय ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पारम्परिक गोंडी रीति-रिवाज से दाम्पत्य सूत्र में बंधे 28 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद व सुखमय दाम्पत्य जीवन की बधाई एवं शुभकामनायें दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने समाज के पदाधिकारियों की मांग पर कसडोल नगर में कंवर समाज सामुदायिक भवन व नगर पंचायत पलारी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50-50 लाख रुपए और ग्राम ओड़ान में बड़ादेव ठाना में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 25 लाख रुपए की घोषणा की। साथ ही ग्राम ओड़ान के शनिमंदिर से बड़ादेव ठाना तक सीसी रोड निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा हमारी सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। गोंडवाना संस्कृति के मानने वाले हमारे सभी आदिवासी भाई प्रकृति के पुजारी हैं। आप लोगों ने जल,जंगल और जमीन की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए इस साल हम लोगों ने 200 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसी तरह जनजातीय समुदाय के समग्र विकास की दिशा में प्रधानमंत्री जनमन योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार

निरंतर काम कर रही है। हम लोगों ने आदिवासी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सम्मान निधि प्रारम्भ किया है, जिसके माध्यम से बैगा, गुनिया और सिरहा को हर साल पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों का आय का एक बड़ा स्रोत वनोपज और तेंदूपत्ता संग्रहण है। हम लोगों ने तेंदूपत्ता संग्रहण का दाम 4 हजार रूपये से बढ़ाकर 5500 रूपये प्रति मानक बोरा किया है। जंगल जाने, वनोपज का संग्रहण करने वाले आदिवासी भाई- बहनों के पैरों में कांटे न चुभे, इसका भी इंतजाम हमारी सरकार ने फिर से किया है। इस साल चरण पादुका वितरण भी किया जाएगा। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका प्रदान करने के लिए बजट में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सामूहिक विवाह बहुत ही अच्छी पहल हैं। इस तरह के आयोजन से न केवल समाज संगठित होता है, बल्कि फिजूलखर्ची पर भी रोक लगती है। उन्होंने कहा कि अभी 10 मार्च को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से 6 हजार से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे प्रदेश में संपन्न हुआ जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस अवसर पर जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक श्री संदीप साहु सहित अन्य गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अफवाहों से बचें एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता.........

रायपुर। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता और वितरण को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ऑयल कंपनियों के पास तीनों ईंधनों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से एलपीजी की बार-बार बुकिंग या पेट्रोल-डीजल का संग्रहण करने से बचने की अपील की गई है। खाद्य विभाग द्वारा एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल के स्टॉक की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलेवार स्टॉक, वितरण और शेष मात्रा की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध भंडारण और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है। किसी भी अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-233-3663, 1967 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771-2511975 व कोरिया जिला में कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया है जहाँ 7648093823 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है ।

धर्मांतरण भाजपा के लिए राजनैतिक हथियार, वह निदान नहीं चाहती........

रायपुर। संवाददाता

धर्म स्वातंर्त्य विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धर्म स्वातंर्त्य विधेयक भाजपा का राजनैतिक प्रोपोगंडा मात्र है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भी भाजपा धर्मांतरण के मामले में केवल राजनीति करेगी। 2006 में भाजपा ने रमन सरकार के समय भी धर्मांतरण को लेकर विधेयक विधानसभा में पारित कराया था। 20 सालों तक वह राजभवन में कैद रहा, जबकि अनेक वर्षों तक केंद्र, राज्य में भाजपा की सरकारे थी, भाजपा केवल जनता को दिखाने के लिए कानून बनाने का स्वांग रचती है। हकीकत में वह धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि वह ध्रुवीकरण

की राजनीति कर सके। भाजपा गारंटी देगी क्या अबकी बार का विधेयक फिर राजभवन में कैद नहीं रहेगा ?प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जबरन धर्मांतरण को सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिये बड़ी समस्या बताया था, तथा कानून बनाने के लिये केन्द्र से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केन्द्र में बैठी मोदी सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ वह पूरे देश में एक कानून बनाये। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को एक साल से अधिक हो गया, लेकिन मोदी सरकार इस पर मौन है। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण को लेकर देश भर में अफवाह फैलाने और राजनीति करने का काम करती है। जब इस मामले में ठोस पहल करने या कानून बनाने की बात आती है तब भाजपा की नीयत में खोट साफ नजर आता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है वह धर्मातरण को लेकर विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ में धर्मातरण को लेकर श्वेत पत्र जारी करें। भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे।

मछली पालन से बदली ग्राम भीतघरा किसान जनक की तकदीर

- आधुनिक तकनीक और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बढ़ी आय, बने प्रेरणा

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़ाकर वैकल्पिक एवं लाभकारी आजीविका अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भीतघरा के किसान जनक यादव ने मछली पालन अपनाकर सफलता की नई मिसाल प्रस्तुत की है। किसान जनक यादव ने परंपरागत धान की खेती के स्थान पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर अपने खेत में दो तालाबों का निर्माण कराया। इसके लिए उन्हें शासन से 4 लाख 20 हजार रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। साथ ही मत्स्य पालन विभाग द्वारा मत्स्य बीज, जाल एवं आइस बॉक्स जैसी आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने आधुनिक पॉन्ड लाइनर तकनीक को अपनाकर मछली पालन शुरू किया, जिससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसान का कहना है कि धान की खेती की तुलना में मछली पालन में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें वर्षभर उत्पादन संभव है, जबकि धान में केवल एक फसल ही ली जा सकती है। जनक यादव पिछले तीन-चार वर्षों से मछली पालन कर रहे हैं और इससे उन्हें निरंतर आय प्राप्त हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस कार्य में अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर आजीविका के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पॉन्ड लाइनर तकनीक से तालाब में पानी का स्तर बनाए रखना आसान होता है। आवश्यकता पड़ने पर पंप के माध्यम से पानी भरकर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन युक्त प्रणाली से मछलियों की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित होती है। किसान जनक यादव ने अन्य किसानों से अपील की है कि वे भी मछली पालन जैसे वैकल्पिक व्यवसाय को अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं और केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि मत्स्य बीज उत्पादन के लिए मार्च, अक्टूबर और नवंबर उपयुक्त समय होता है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। किसान जनक यादव की यह सफलता कहानी दर्शाती है कि आधुनिक तकनीक, विभागीय मार्गदर्शन और योजनाओं के प्रभावी उपयोग से किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।

बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया-कांग्रेस.........

रायपुर। संवाददाता

बढ़े बिजली बिल ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि चार महिने से आ रहे बेतहाशा बढ़ा बिजली बिल से राज्य का हर नागरिक परेशान है। 200 यूनिट हाफ बिजली योजना से भी कोई राहत नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार भूपेश सरकार के समय शुरू की गयी बिजली बिल हाफयोजना को फिर शुरू करें, ताकि जनता को बढ़े बिजली बिल में कुछ राहत मिल सके। बिजली बिल हाफ योजना बंद करने के कारण जनता बिजली के बिल नहीं पटा पा रही उनकी लाईन काटी जा रही। प्रदेश

में हजारो उपभोक्ताओं की बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की नाकामी लापरवाही और मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्रदेश के लोगों के लिए बिजली कटौती और मंहगी बिजली बड़ी समस्या बन गई है। राज्य बनने के बाद प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में है। सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया जिससे लोगों के बिजली के बिल दुगुना से भी अधिक आ रहा। महंगी बिजली के बाद भी सरकार जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में आठ-नौ घंटे तक हो रही बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही, लोग बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बिजली उत्पादन का प्रमुख घटक कोयला है। कोयले पर लगने वाला सेस कम हो गया है, जिसके कारण कोयले का दाम न्यूनतम 400 रू. कम हो गया है।

बीपी मशीन की आड़ में कुरियर से मंगाया कोकीन

रायपुर। राजधानी रायपुर की क्राईम एवं सायबर टीम ने मादक पदार्थ कोकीन मंगाने बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे आरोपी कृष्ण गोपाल अग्रवाल गिरफ्तार हो गया है। आरोपी द्वारा बीपी मशीन की आड़ में कुरियर सें कोकीन मंगाया गया था। बताा दें कि अवैध एवं प्रतिबंधित मादक पदार्थो, प्रतिबंधित नशीली टेबलेट एवं सिरप तथा सूखे नशे की तस्करी, खरीदी-बिक्री, नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं साईबर) रायपुर के पर्यवेक्षण तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (क्राईम एवं साईबर) रायपुर के नेतृत्व में 10 सदस्यीय एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। उक्त टीम को एंड टू एंड एवं फाइनेंशियल इनवेस्टिगेशन, सोर्स प्वाइंट, डेस्टिनेशन प्वाइंट पर प्रभावी कार्यवाही करने सहित स्त्रोत के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर उनके विरूद्ध विधिसंगत विधिवत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना देवेन्द्रनगर क्षेत्रांतर्गत नारायणा हॉस्पिटल सेक्टर 05 के पास 01 व्यक्ति चारपहिया वाहन में अपने पास मादक पदार्थ कोकीन रखा है तथा ग्राहक की तलाश कर रहा है। उक्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपायुक्त (क्राईम एण्ड साइबर) स्मृतिक राजनाला एवं पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) उमेश प्रसाद गुप्ता द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं प्रभारियों को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों को मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026

9,800 से अधिक धावकों के साथ रचा इतिहास,वैश्विक मंच पर चमका बस्तर

- समृद्ध और विकसित बस्तर बनाने का प्रयास : वनमंत्री केदार कश्यप
- देव ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ हाफमैराथन आयोजन के बाद बस्तर हैरिटेज मैराथन का आयोजन शांति, विकास और समृद्धि का नया अध्याय है

रायपुर/ संवाददाता

बस्तर की ऐतिहासिक और नैसर्गिक धरा उस समय गौरवशाली क्षण की साक्षी बनी, जब 'बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026' में उत्साह का अभूतपूर्व जन सैलाब उमड़ा और 9,800 से अधिक पंजीकृत धावकों ने भाग लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप, बढ़ती शांति और शासन की 'पूना मारगेम' जैसी पुनर्वास नीतियों की सफलता का जीवंत प्रतीक बनकर उभरा। बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026' बस्तर के जगदलपुर स्थित लालबाग से प्रारम्भ होकर चित्रकोट जल प्रपात के समीप समापन पश्चात आयोजित समारोह के अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने मैराथन के विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि समृद्ध और विकसित बस्तर बनाने का प्रयास के साथ बस्तर क्षेत्र में बस्तर हैरीटेज मैराथन 2026 का आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा। बस्तर बदल रहा है, बस्तर जो चार दशक से अशांत क्षेत्र रहा अब शांति का गढ़ बन रहा है। यहाँ के युवा खेल गतिविधियों के साथ ही देश के प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफल हो रहे हैं। शांति के इस माहौल में बस्तर मैराथन में देश-विदेश के कई राज्यों और प्रदेश के अन्य जिलों तथा बस्तर संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए।उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई देते भविष्य में पुनः भव्य आयोजन की आशा व्यक्त की। समारोह में विधायक श्री किरण सिंह देव ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में अबूझमाड़ हाफ मैराथन आयोजन के बाद बस्तर हैरिटेज मैराथन का आयोजन शांति, विकास

और समृद्धि का नया अध्याय है । अब बस्तर में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति दी जाएगी इसी का एक प्रयास मैराथन का आयोजन है । इस अवसर पर सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप और विधायक श्री विनायक गोयल ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैराथन के विजेताओं को बधाई दी। 'बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026' का मुख्य आकर्षण 42 किलोमीटर की फुल मैराथन रही, जिसकी शुरुआत जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान से हुई और समापन 'भारत का नियाग्रा' कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात के तट पर हुआ। आयोजन को समावेशी बनाने के उद्देश्य से इसे 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी की श्रेणियों में विभाजित किया गया था। 21 किमी दौड़ पोटानार तक, 10 किमी दौड़ कुम्हरावंड तक, जबकि 5 किमी की दौड़ लालबाग से दलपत सागर रानीघाट तक आयोजित की गई, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन द्वारा 25 लाख रुपये की आकर्षक इनामी राशि घोषित की गई थी। साथ ही स्थानीय धावकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर देने हेतु 'बस्तर कैटेगरी' का विशेष प्रावधान रखा गया और बस्तर जिले के निवासियों के लिए पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क रखा गया। विशेष बात यह रही कि इस मैराथन में मांझी- चालकी समुदाय के लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे आयोजन की सामाजिक समावेशिता और अधिक सुदृढ़ हुई। इस भव्य आयोजन ने न केवल खेल भावना को प्रोत्साहित किया, बल्कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति, शांति और विकास की नई तस्वीर को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्री संजय पांडेय, ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री बलदेव मंडावी, सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि, मांझी- चालकी, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आई जी श्री सुंदरराज पी., कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।

संपादकीय

भारत सरकार की चुप्पी

भारत सरकार की चुप्पी देश में लाचारी का बोध पैदा कर रही है। भारतीय विदेश नीति ऐसे मुकाम पर क्यों आ पहुंची, जिसमें ना कोई स्पष्ट रुख दिखता है, और ना ही देश की स्वतंत्र पहचान की रक्षा करने की कोई रणनीति?
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया, लेकिन विपक्षी सदस्यों को उस पर सवाल पूछने या स्पष्टीकरण मांगने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष इस बेहद गंभीर संकट पर संसद में बहस चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष को उस पर एतराज है! नतीजतन, सरकार जितना कहना चाहती थी, उसके अतिरिक्त जो असमंजस लोगों के मन में हैं, उस पर अस्पष्टता बनी रह गई है। ऐसी कुछ बातों को बाद में कांग्रेस ने अपने सार्वजनिक बयान में शामिल किया। इसमें ध्यान दिलाया गया कि विदेश मंत्री ने ईरानी नौसेना के जहाज दिना को भारतीय रणनीतिक क्षेत्र में डुबोने की अमेरिकी कार्रवाई पर विरोध नहीं जताया, ना ही उन्होंने एक संप्रभु राष्ट्र के राज्य-प्रमुख की हत्या की निंदा की। ना ही उन्होंने जारी युद्ध से भारत के सामने आईं गंभीर भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के बारे में कोई राय रखी। कांग्रेस ने कहा कि इस समय विश्व प्रणाली में आ रहे बुनियादी परिवर्तन के मद्देनजर भारत को क्या नजरिया अपनाना चाहिए, विदेश मंत्री इस संबंध में भी कोई अंतर्दृष्टि सामने रखने में विफल रहे। ये वो बातें हैं, जो भारतीय जनमत के एक बड़े हिस्से के मन में हैं। जनमत का यह हिस्सा इनको लेकर ना सिर्फ चिंतित है, बल्कि वैश्विक विमर्श में भारत की अनुपस्थिति देखकर आहत भी है। यह व्यग्रता तब और बढ़ जाती है, जब अमेरिकी अधिकारी भारत को 'अनुमति देने' की बात करते हैं और उनकी 'निर्देशों' का पालन करने की भारत की 'अच्छी भूमिका' की तारीफ करते हैं। उनमें से कोई अधिकारी जब भारत की जमीन पर आकर ये एलान करता है कि अमेरिका चीन की तरह भारत के उदय में सहायक नहीं बनेगा, तो ये बेचैनी आक्रोश में बदल जाती है। इन सब पर भारत सरकार की चुप्पी देश में लाचारी का बोध पैदा कर रही है। ऐसे में ये सवाल प्रासंगिक है कि आखिर भारत की विदेश नीति ऐसे मुकाम पर क्यों आ पहुंची, जिसमें ना कोई स्पष्ट रुख नजर आता है, और ना ही देश की स्वतंत्र पहचान की रक्षा करने की कोई रणनीति?

यह नया भारत है यहां इस्तीफा नहीं होता

हरिशंकर व्यास

जिस तरह के कपड़ों पर से जिद्दी दाग हटाने वाले डिटरजेंट और वॉशिंग मशीन आ गए हैं उसी तरह राजनीति में भ्रष्टाचार के दाग मिटाने वाली एक बेहद कारगर वॉशिंग मशीन आ गई है। वह वॉशिंग मशीन भाजपा की है। भाजपा के अलावा बाकी हर पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं और वंशवादी हैं। भाजपा के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के अलावा सब भ्रष्ट हैं। चाहे वह न्यायपालिका के शीर्ष पर बैठे लोग हों या विपक्ष की राजनीति के शीर्ष लोग हों या मीडिया के लोग हैं, सब भ्रष्ट हैं। हां, ईमानदार और साफ सुथरी सिर्फ भाजपा और उसके नेता हैं। अगर कोई कथित भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है तो तत्काल उसके दाग धुल जाते हैं और वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह से अगर भाजपा के किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगता हो तो आरोप लगाने वाले कितना भी विश्वसनीय क्यों न हो और आरोप कितने भी गंभीर क्यों नहीं हों उनके दाग उस पर नहीं लगते हैं। किसी भी कीमत पर भाजपा के किसी नेता के ऊपर दाग नहीं लग सकता है। इसके लिए भाजपा ने 'हमारे यहां इस्तीफ नहीं होता' का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कितना भी गंभीर आरोप हो भाजपा के लोग इस्तीफा नहीं देते। वैसे इस्तीफा देना किसी अपराध की सजा नहीं है। लेकिन यहां वह भी नहीं होता है। जैसे अभी एपस्टीन फाइल्स को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा है। इस्तीफा हो रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं। ब्रिटेन में तो राजा के भाई को ही गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में ब्रिटिश सरकार के राजदूत रहे नेता की गिरफ्तारी हुई है। प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ और मीडिया सलाहकार का इस्तीफा हुआ है। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। नार्वे के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। लेकिन भारत में? भारत में जिसके ऊपर आरोप लगे, एपस्टीन के साथ जिसके सैकड़ों ईमेल सामने आए और कई बार मुलाकातों का ब्योरा सामने आया वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने को बेदाग बताता रहा और आरोप लगाने वालों को ही भ्रष्ट, बेईमान बताने लगा। मीडिया का एक समूह केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा मांगने या कम से कम सवाल पूछने की बजाय मंत्री के साथ साथ दुनिया के सबसे नीच सेक्स अपराधी एपस्टीन का बचाव करने लगा। केंद्रीय मंत्री और देश के बड़े कारोबारी का नाम एपस्टीन के साथ जुड़ा लेकिन दिन भर शुचिता, ईमानदारी, त्याग, तपस्या आदि की बात करने वाले भारत में किसी के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। यह नया भारत है यहां इस्तीफा नहीं होता है। बहरहाल, वॉशिंग मशीन की कहानी अब घर घर पहुंच गई है। भाजपा के बड़े नेता पहले दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। किसी पर 70 हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो किसी पर चार हजार करोड़ रुपए का आरोप लगाते हैं। किसी को कांग्रेस आलाकमान का एटीएम बताते हैं तो किसी को दूसरी प्रादेशिक पार्टी के नेता का एटीएम बताते हैं। इसके बाद उसी नेता को गाजे बाजे के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। इस तरह उसके भ्रष्टाचार से लड़ाई संपन्न होती है। क्योंकि भाजपा में शामिल होते ही उस नेता के दाग धुल जाते हैं और वह ईमानदार हो जाता है। पुराने अधिकारी और पुराने न्यायिक अधिकारी, पहले चाहे जैसे रहे हों, भाजपा में जाते ही ईमानदार हो जाते हैं। सो, ईमानदार सिर्फ भाजपा और उसकी सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री आदि हैं। बाकी पार्टियों के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब बेईमान और भ्रष्ट हैं। उनके अपने आरोप धोने का एक ही रास्ता है कि वे भाजपा में शामिल हो जाएं। न्यायपालिका से भी उनके दाग नहीं धुल सकते हैं तो भाजपा में शामिल हो से दाग धुल जाते हैं।

क्या पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सवर्णो के राजनीतिक-सामाजिक भविष्य को तय करेंगे?

कमलेश पांडे

देश के पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसके मतदान/परिणाम भाजपा नीत एनडीए की भावी रीति-नीति और सवर्णों के सामाजिक-राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। बताया जाता है कि यदि इन चुनावों को भाजपा नीत गठबंधन जीत जाता है तो वह ओबीसी-दलित वोटरों को रिझाने के लिए सवर्ण विरोधी एजेंडों को इत्मीनान पूर्वक धार देगा! ऐसा इसलिए कि सामान्य जातियों से जुड़े सवर्ण वोटर ही भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रहते हुए भी जिस तरह से सवर्ण विरोधी यूजीसी इक्विटी बिल लाया गया है, उससे सामान्य जातियों के लोग अर्थात सवर्ण समुदाय का एक बड़ा तबका अपनी मुख्य पार्टी भाजपा से काफी नाराज हैं और बदलती राजनीति के बीच वे किधर करवट लेंगे, यह बात पूरी तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए भाजपा कांग्रेसी राज और समाजवादी राज की दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक व भाषाई क्षेत्र सम्बन्धी नीतियों को और अधिक धार दे रही है। आरक्षण, जातीय जनगणना, एससी-एसटी एक्ट से जुड़े पदोन्नति प्रावधान, कमाऊ मंदिर संचालन जैसी नीतियों में पहले की सरकारों में और अब की सरकार में कोई अंतर नहीं आया है।

कोढ़ में खाज यह कि भाजपा अपने हिंदुत्व के एजेंडे से भटकती प्रतीत हो रही है। ऐसे में सत्ता के जातीय, सांप्रदायिक और भाषाई-क्षेत्रवाद की मानसिकता में कोई बदलाव न देख देश का सामाजिक इंजन वर्ग यानी सवर्ण समुदाय भाजपा से काफी नाराज है और यूजीसी इक्विटी बिल ने आग में घी का काम किया है।

चूंकि सवर्ण वोट कभी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों का भी कोर वोट बैंक हुआ करता था, और इनकी दलित-ओबीसी आरक्षण व अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियों से आजिज होकर भाजपा के आकर्षक मंडल विरोधी कमण्डलवाद पर फिदा हो चुका था, वह मोदी-शाह युग में एक के बाद दूसरे झटके लगते रहने से सियासी विकल्प ढूंढ रहा है। चूंकि भाजपा नेतृत्व पूंजीपतियों के इशारे पर ब्राह्मण-राजपूत नेतृत्व को दरकिनार करते हुए ओबीसी-दलित नेतृत्व को मजबूत कर रहा है, इससे भी सवर्ण वर्ग में नाराजगी है। यही वजह है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भाजपा के खिलाफपनपे सवर्ण प्रतिरोध को पूरी तरह से अंदर ही अंदर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका दलित-ओबीसी-अल्पसंख्यक कोर वोट बैंक नाराज भी न हो और सवर्ण भी उनकी ओर लौट जाएं, ताकि अबतक की हारी हुई बाजी को पुन: जीता जा सके और यत्र तत्र जीती हुई बाजी को बरकरार रखाक जा सके! हालांकि, अब वे अपनी कोशिशों में कितने कामयाब होंगे, यह तो मतदान/मतगणना बाद ही पता चल पाएगा।

वहीं, कतिपय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देश के पश्चिम बंगाल समेत असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चुनाव परिणाम सवर्णों के सामाजिक-राजनीतिक भविष्य को तय नहीं करेंगे, भले ही भाजपा इन चुनावों में पश्चिम बंगाल और असम जीत जाए और तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी में पहले से ज्यादा मजबूत होकर जीते। क्योंकि यूजीसी इक्विटी बिल के बाद उपजे सवर्ण जनाक्रोश को डैमेज-कंट्रोल करने के लिए भाजपा-आरएसएस के रणनीतिकार जुट गए हैं, हालांकि उन्हें भी यह आशंका है कि ये चुनाव भाजपा के सवर्ण वोट बैंक के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा की घड़ी हैं! वहीं, भाजपा की ओर कितने दलित-ओबीसी वोटर लौटते हैं, इससे भाजपा को सियासी तंदुरुस्ती मिलेगी।

भाजपा की सवर्ण लॉबी का कहना है कि अब भी सवर्ण वोट पार्टी के कोर सपोर्टर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास भाजपा से उम्दा विकल्प मौजूद नहीं है। जबकि भाजपा अपनी चुनावी जीत के लिए दलित, आदिवासी और ओबीसी वोटों पर ही निर्भर करती है। इसलिए वह सभी समुदायों के बीच राष्ट्रवादी तालमेल बिठाने में जुटी हुई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देश, भारत के खिलाफ नहीं खड़े हों, इसलिए भाजपा ने भी कुछ बदलावों के साथ अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीतियों को अपना लिया है।

मसलन, यदि 5 राज्यों में हो रहे चुनावों की चुनावी पृष्ठभूमि पर नजर डाली जाए तो 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए मतदान 23-29 अप्रैल 2026 को होंगे। वहीं असम की 126 विधानसभा सीटों, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों, केरल की 140 विधानसभा सीटों और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। इन चुनावों में भाजपा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और असम पर फोकस कर रही है। क्योंकि जहां पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 77 सीटें मिलीं थी। वहीं, असम में भाजपा की सत्ता बरकरार रहा गई थी और अभी वहां भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है।

इसलिए, जहां तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सवर्णों की भूमिका की बात है तो भाजपा को सवर्ण यानी ब्राह्मण, कायस्थ, वैद्य आदि से मजबूत समर्थन मिलता बताया जा रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर सभी जातियों व धर्मों को मिलाकर 61त्न सवर्ण वोट हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा '5त्न हिंदू वोट फॉर्मूला' से सवर्णों को 'सनातनी' के रूप में साध रही है। जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व में सूबाई सत्ता के शीर्ष पर सवर्ण कायम हैं, जबकि जीत के पीछे अल्पसंख्यक-दलित-आदिवासी-ओबीसी वोट मुख्य हैं।

इसलिए भाजपा भी पश्चिम बंगाल में सवर्णों को टीएमसी की सत्ता से खींचकर अपनी ओर करना चाहती है और ओबीसी-दलित-आदिवासी वोटरों को भी अपने पाले में करने में जुटी हुई है, जबकि अल्पसंख्यक वोटों के रायता फैलाने हेतु उसके गुप्त इशारे पर वहां की लोकल अल्पसंख्यक पार्टी ताल ठोक चुकी है। वहीं बंगाल अस्मिता का सवाल कितना मुखर होगा, घुसपैठियों का मुद्दा कितना रंग लाएगा, वह मतदान ट्रेंड और चुनाव परिणाम से ही पता चलेगा। वहीं, जहां तक पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के परिणाम की बात है तो भाजपा की जीत से सवर्णों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन उनका सामाजिक भविष्य भाजपा की राष्ट्रीय नीतियों यथा-आरक्षण, जाति जनगणना आदि पर ही निर्भर करेगा। वहीं, असम में भी यही बातें लागू होंगी, क्योंकि वहाँ तो भाजपा पहले से ही सत्ता में है। वहीं, तमिलनाडु और केरल में सवर्ण प्रभाव कम है, इसलिए 5 राज्यों की जीत से सवर्ण गठबंधन मजबूत होगा, न कि सवर्णों का राजनीतिक-सामाजिक भविष्य तय होगा। उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि के भावी विधानसभा और आम चुनाव 2029 के रुझान, मतदान और चुनाव परिणाम वास्तविक तौर पर सवर्णों के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को तय करेंगे। यही वजह है कि भाजपा की पश्चिम बंगाल में जीत से सवर्ण ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर भी सीधा असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के नीति क्षेत्र में आता है। राज्य स्तर पर भाजपा सवर्ण समर्थन को मजबूत करने वाली नीतियां ला सकती है, लेकिन 10% आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण (EWS) आरक्षण राष्ट्रीय कानून है। यदि इसे पश्चिम बंगाल में भी लागू करवाया जाता है तो यह और भी अच्छी बात होगी। जहां तक वर्तमान आरक्षण स्थिति की बात है तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान आरक्षण 39त्न हैं, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) 22%, अनुसूचित जनजाति (ST) 6%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 10%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 1% है, जो 50% की अनुमन्य सीमा से 11% कम है। चूंकि भाजपा केंद्र में ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण को साल 2019 से लागू कर चुकी है, जो सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर है, जाति आधार पर नहीं। यही वजह है कि भाजपा यदि पश्चिम बंगाल की सत्ता में आती है तो इसका संभावित प्रभाव राज्य नीति पर भी पड़ेगा। चर्चा है कि पश्चिम बंगाल की जीत पर भाजपा ईडब्ल्यूएस (EWS) कोटा बढ़ा सकती है और सवर्ण-केंद्रित योजनाएं जो शिक्षा, नौकरी से जुड़ी हैं, वहां ला सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा बाधा बनेगी। जहां तक राजनीतिक बात है तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से सवर्ण वोट मजबूत होंगे, लेकिन दलित-ओबीसी विरोध बढ़ सकता है, जैसा यूजीसी नियमों पर देखा गया। इसका राष्ट्रीय लिंक यह है कि पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा नीत एनडीए को मजबूती देगी, जिससे संसदीय बहुमत से ईडब्ल्यूएस विस्तार संभव है, पर सुप्रीम कोर्ट की चुनौती बनी रहेगी। चुनाव पूर्व सर्वे के रुझान चुगली कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सवर्ण वोटर भाजपा के लिए कोर समर्थन आधार बने रहेंगे, लेकिन उनकी भूमिका निर्णायक से अधिक सहायक होगी। ताजा ओपिनियन पोल्स के अनुसार, सवर्ण हिंदू वोटों का लगभग 33% भाजपा को मिल सकता है, जबकि 20% अभी अनिर्णय की स्थिति में है, यानी अनडिसाइडेड हैं। जहां तक सवर्ण वोटों के आकार की बात है तो पश्चिम बंगाल में हिंदू सवर्ण यानी ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य मतदाता, कुल मतदाताओं का करीब 15-20% हैं, जो मुख्यत: शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। भाजपा इन्हें 'सनातनी एकता' के जरिए साध रही है, और 2021 के विधानसभा चुनाव में 68% हिंदू वोट, जिनमें सवर्ण वोट प्रमुख रहे, भाजपा को मिले थे, जिससे वह 77 सीटें जीत पाई है। जहां तक रणनीतिक महत्व की बात है तो भाजपा का '5% हिंदू वोट स्विंग' फॉर्मूला सवर्णों समेत हिंदू वोटों पर केंद्रित है, और टीएमसी से शिफ्ट का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि सवर्ण अनडिसाइडेड हैं, मुस्लिम-टीएमसी समर्थन 23त्न हैं, इसलिए मतुआ/ओबीसी वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि एसआईआर (SIR) विवाद से मतुआ वोट प्रभावित हो रहे, जो सवर्ण-केंद्रित भाजपा की रणनीति को कमजोर कर सकता है। वहीं टीएमसी (TMC) सवर्णों को 'ब्राह्मण वोट' के रूप में लुभा रही, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हैं। लेकिन सवर्णों पर भाजपा का पारंपरिक दबदबा भी बरकरार है। लिहाजा, सवर्णों का वोट विभाजित होना तय है।

रही बात असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के 2026 विधानसभा चुनावों में सवर्ण वोटरों की भूमिका की तो यह राज्य-विशेष परिस्थितियों के अनुरूप होगी। मुख्य रूप से ये भाजपा या एनडीए (NDA) के पक्ष में काम कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक प्रभाव सीमित रहेगा। जहां तक असम की बात है तो यहां सवर्ण वोटरों में मुख्यत: ब्राह्मण-अग्रवाल वैश्य हैं, जो कुल मतदाताओं के 10-12% हैं और भाजपा के मजबूत समर्थक माने जाते हैं। यहां पर एनडीए (NDA) की भाजपा ने राज्य की 89 सीटें जीत करके अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंत विश्वसरमा की लोकप्रियता के साथ लोग एकजूट हैं। वहीं, केरल में सवर्ण वोटरों में नायर, ब्राह्मण प्रमुख हैं जो हिंदू वोट बैंक का बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन यहां पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम 27% और ईसाई 18% अबतक निर्णायक होते आए हैं। जबकि इस बार भाजपा को मामूली समर्थन मिल सकता है, पर यहां सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) और मुख्य विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (DF) के द्वंद्व में भाजपा की राजनीतिक भूमिका गौण ही रहेगी, या फिर वह मजबूती और रणनीतिक कौशल से लड़ी तो किंग मेकर भी बन सकती है। त्रिस्तरीय चुनाव परिणामों से तो यही पता चलता है। जहां तक तमिलनाडु की बात है तो यहां सवर्ण प्रभाव न्यून है, जबकि द्रविड़ राजनीति में ओबीसी/दलित प्रमुख हैं। इसलिए भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन को सीमित फायदा मिलेगा। जबकि डीएमके-कांग्रेस गठबंधन का वर्चस्व, विजय की ओर है। वहीं टीवीके (TVK) एक नया फैक्टर बन चुका है। यदि इसे चुनावी सफलता मिलती है तो भाजपा गठबंधन वहां भी किंगमेकर की भूमिका निभा सकता है।

जहां तक पुडुचेरी की बात है तो यहां सवर्ण वोटर में वन्नियार, ब्राह्मण हैं जो एनडीए (एन.रंगासामी) के पक्ष में हैं, और 30 सीटों में शहरी क्षेत्रों पर फोकस करते हैं। ये कांग्रेस-बीजेपी मुकाबले में सहायक हैं।

बताया जाता है कि 2026 में इन 5 राज्यों यथा-पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में सवर्ण ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुख्य मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण केंद्र स्तर पर स्थापित नीति है, जबकि राज्य चुनाव स्थानीय मुद्दों, जैसे बंगाल में घुसपैठ के खिलाफध्रुवीकरण, असम में प्रवासी आदि पर केंद्रित रहेंगे। इसका प्रमुख कारण है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग आरक्षण (10% ईडब्ल्यूएस) जो 2019 से कानूनी रूप से लागू है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे मान्य करार दिया गया है।

वहीं, हालिया चुनावी विमर्श में पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर और यूजीसी इक्विटी बिल 2026 जैसे नए विवाद उभरे हैं, जो हिंदुओं खासकर सवर्णों के सियासी मूड को बदल सकते हैं, न कि पुरानी नीति पर वह कायम रहेंगे। इसलिए राज्यवार संभावना है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू एकता वनाम टीएमसी (TMC) का पारंपरिक वोट समीकरण हावी रहेगा, इसलिए यहां ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण का मुद्दा गौण रह जाएगा। वहीं असम में भाजपा नीत एनडीए की सत्ता, सूबाई/राष्ट्रीय रक्षा नीति और जातिगत गठजोड़ पर टिकी रहेगी। जबकि केरल/तमिलनाडु में अल्पसंख्यक और क्षेत्रीय ओबीसी समीकरण हावी रहेंगे। वहीं, पुडुचेरी में गठबंधन राजनीति भारी पड़ेगी। इसलिए इन चुनावों में असम में जहां भाजपा को अपनी सत्ता बरकरार रखनी है, वहीं पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करना उसकी प्राथमिकता में है। यदि वह तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ सत्ता पाने में कामयाब होती है तो यह उसकी सियासी कौशल का ही नतीजा होगा, जिसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मशहूर माने जाते हैं और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बताए जाते हैं।

सरकारी व्यवस्था पर कम हुआ भरोसा बढ़ेगा

सुनील दास

एक सरकार की गलतियों के कारण सरकारी व्यवस्था पर राज्य के लोगों का,राज्य के युवाओं का भरोसा कम हो जाता है तो यह बद से बदतर स्थिति होती है।ऐसे में राज्य में ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है।कई लोग बिना मेहनत,पहुंच व पैसे के बल पर प्रतियोगी परीक्षा में पास हो जाते है या पास कर दिए जाते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले युवाओं को बहुत निराशा होती है।उनकी मेहनत व योग्यता का कोई मतलब नही रह जाता है।राज्य में जब भी प्रतियोगी परीक्षा होती और उसमें जो लोग पास होते हैं माना यही जाता है कि वह गड़बड़ी करके पास हुए हैं, पैसे व पहुंच के बल पर पास हुए हैं।जब इसे सरकार रोकने का प्रयास नही करती है तो माना जाता है कि सरकार के लोग ही इसके पक्ष में हैं,सरकार भी इसके पक्ष में है। जब सीएम से शिकायत की जाए कि प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो सीएम शिकायत करने वालों से सबूत मांगे तो युवाओं को बहुत निराशा होती है।

ऐसे में राज्य के लोग ऐसी सरकार व ऐसी सीएम को चुनाव आता है तो बदलने का मन बनाते हैं और बदल कर संदेश देते हैं कि उन्हें ऐसी सरकार व व्यवस्था नहीं चाहिए जहां प्रतियोगी परीक्षा में वही पास हों जिनकी पहुंच है या जिनके पास पैसा है। पुरानी सरकार की जगह जब नई सरकार आती है तो उसे पता रहता है कि जनता

ने पुरानी सरकार को क्यों बदला और वह नई सरकार से क्या चाहती है।ऐसे में नई सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वह राज्य के युवाओं व राज्य के लोगों के प्रतियोगी परीक्षा के रिजल्ट पर कम हो रहे भरोसे को बनाने के लिए कोई उपाय करे। इसकी शुरुआत साय सरकार ने पीएससी में हुए भ्रष्टाचार की जांच करा कर की है और कई लोगो की गिरफ्तारी हुई है। जांच से ही पता चला कि पीएससी की परीक्षा में कैसे गड़बड़ी की गई है।इससे ही सरकार को पता चला कि भविष्य में गड़ब़ड़ी रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

साय सरकार ने यह व्यवस्था की कि यदि पीएससी की परीक्षा में पीएससी परीक्षा लेने वाले प्रमुख लोगों के घर के या परिवार के कोई परीक्षा दे रहे है तो उनको पद से हटाया जाएगा यानी वह खुद ही पद पर नही रहेगा। क्योंकि बड़े पद पर रहने वालों ने ही अपने परिवार के लोगों को पीएससी में पास कराने के लिए सारी गड़बडी की थी।इसके बाद कानून बनाकर दंड की व्यवस्था करना भी जरूरी था इसलिए साय सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली व गड़बड़ी रोकने लिए विधेयक-26 लाया गया है।नए कानून के तहत लोक सेवा प्राधिकरण का गठन होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की मानिटरिंग करेगा। नए कानून के तहत यदि कोई संस्थान,प्रबंधन या सेवा प्रदाता प्रश्नपत्र लीक करता है या धोखाधड़ी में लिप्त पाया जाता है तो उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना व दस साल की सजा हो सकती है।विधेयक में परीक्षार्थियों के लिए भी गाइड लाइन तय की गई है।अगर कोई छात्र परीक्षा में नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और एक से तीन साल तक सरकारी परीक्षा में शामिल होने पर बैन कर दिया जाएगा।

सीएम साय ने कहा है कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही परीक्षा व्यवस्था में व्याप्त गड़बडियों पर करारा प्रहार किया। पीएससी घोटाले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की गई। धांधली करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी गई। सभी प्रतियोगी परीक्षाओ में शतप्रतिशत पारदर्शिता तय करने और अभ्यर्थियों के हित में कई अहम फैसले किए गए।इसी कड़ी में यह नया विधेयक लाया गया है।इसके माध्यम से भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार व धांधली को समाप्त किया जाएगा।इस कानून के लागू होने के बाद अब कोई भी व्यक्ति युवाओं के सपने से खिलवाड़ नही कर सकेगा और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को उनका उचित अधिकार मिलेगा। अब स्पष्ट व कठोर प्रावधानों के कारण नकल गिरोह,पेपरलीक करने वालों तता फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफप्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।

किसी पार्टी का शिखर पुरुष जैसा होता है, वह जैसा काम करता है, उससे राज्य में नेतृत्व को वैसा काम करने की प्रेरणा मिलती है।पीएम मोदी ने दस सालो में कई क्षेत्रों में पिछले कई दशकों में जो सुधार नहीं हुए थे वह सुधार किए है और देश में कई क्षेत्रों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है, बेहतर बनाया है इससे लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सुविधाएं मिल रही है।केंद्र में पीएम मोदी के सुधारों से प्रेरित होकर छत्तीसगढ के सीएम साय ने भी राज्य मे कई क्षेत्रों में सुधार के काम किए हैं और उसका रिजल्ट भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। साय सरकार ने पिछली सरकार की गलतियों से सबक लिया है और हर क्षेत्र में सुधार का काम किया है ताकि उनकी सरकार की तुलना जब पिछली सरकार से हो तो लोगों को साफ दिखाई दे कि यह सरकार वैसी कोई गलती नहीं कर रही है जैसी गलतियां पिछली सरकार के समय हुई थीं।

संक्षिप्त-खबर

जिले में फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू, पहले चरण की तैयारियां तेज

मुंगेली(समय दर्शन) भारत की आगामी जनगणना 2027 के प्रथम चरण को सफ्लतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में फील्ड ट्रेनरों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। यह प्रशिक्षण 25 मार्च 2026 तक प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 05 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का आयोजन पीएम श्री स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय, दाउपारा मुंगेली में किया गया है, जिसमें जिले के सभी फील्ड ट्रेनरों की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 01 मई से 30 मई 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों द्वारा घर-घर जाकर संपादित किया जाएगा, जिन्हें पूर्व में फील्ड ट्रेनरों द्वारा विधिवत प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनरों द्वारा फील्ड ट्रेनरों को जनगणना की विस्तृत प्रक्रिया, डेटा संग्रहण के तरीके, तकनीकी उपयोग तथा सर्वेक्षण से संबंधित सभी आवश्यक बिंदुओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया जा रहा है कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें टैबलेट, मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी। जनगणना के प्रथम चरण में कुल 33 प्रश्नों के माध्यम से मकानों से संबंधित विभिन्न जानकारियां एकत्रित की जाएंगी। इसमें मकान की स्थिति, निर्माण सामग्री, उपलब्ध सुविधाएं जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, वाहन आदि के साथ-साथ अन्य आधारभूत जानकारी शामिल रहेगी। एकत्रित जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल शासकीय योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में किया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत फील्ड ट्रेनर अपने-अपने क्षेत्र के प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, जिसके बाद वे निर्धारित अवधि में घर-घर जाकर जानकारी संकलित करेंगे। आगामी वर्ष फरवरी 2027 में जनगणना का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को कहा कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान करें और सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाया जा सके।

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर की गई कार्रवाई: 12 ट्रैक्टर व 3 हाइवा जब्त

जांजगीर-चांपा (समय दर्शन)) कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु खनिज विभाग के उडनदस्ता दल द्वारा जिले के केवा, नवापारा, भादा, पुछेली, पिपरदा, बम्हनीडीह, केराकछार, खोरसी, देवरघटा, शिवरीनारायण आदि क्षेत्र में खनिजो के अवैध परिवहन, भण्डारण, उत्खनन करने वाले वाहनो व स्थानो का औचक जांच किया गया।

खनि अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान जिले में खनिज रेत के अवैध परिवहन करते कुल 15 प्रकरण दर्ज कर जब्ती की कार्रवाई की गई है। जिसमें खनिज रेत अवैध परिवहन के 09 प्रकरण (06 ट्रेक्टर, 03 हाईवा), मिट्टी (ईंट) के 03 प्रकरण (03 ट्रेक्टर) तथा खनिज चूनापत्थर अवैध परिवहन के 03 प्रकरण (03 ट्रेक्टर) शामिल है। जप्त वाहनों को जिले के जांच क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना, शिवरीनारायण, पामगढ़, बिर्रा, पंतोरा तथा पुलिस लाईन जांजगीर में सुरक्षार्थ रखा गया है।

खनिजो के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खांन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में खनिज विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही की जा रही है, जो कि आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी।

विश्व क्षय दिवस: टी बी मुक्त पंचायत अभियान : टी.बी मुक्त 74 ग्राम पंचायतों का हुआ सम्मान

जनभागीदारी और जागरूकता से ही टी.बी. मुक्त अभियान को सफ्लता मिलेगी सफ्लता - विधायक मोहले

मोबाईल टी.बी एक्सरे रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

मुंगेली(समय दर्शन) विश्व क्षय दिवस 2026 के अवसर पर जिले में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (100 दिवसीय अभियान ''द्वितीय चरण) के तहत जनदर्शन सभाकक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मुंगेली विधायक पुन्नूलाल मोहले मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक मोहले ने कहा कि वर्ष 2026 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया है और इस दिशा में मुंगेली जिले द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी और जागरूकता से ही इस अभियान को सफ्लता मिलेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय ने 24 मार्च को विश्व टी बी दिवस के अवसर पर जिले को टी.बी मुक्त बनाने एवं संकल्प लेने की बात कहीं।

सीएमएचओ श्रीमती शीला साहा ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में 11 हजार 807 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें 824 टीबी मरीजों की पहचान हुई। इनमें से 97 प्रतिशत मरीजों को सफ्लतापूर्वक उपचार देकर रोग मुक्त किया गया। 804 मरीजों को निक्षय मित्र योजना के माध्यम से पोषण आहार भी उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो सके। भारत को टी.बी मुक्त करने के लिए अभियान का संचालन किया जा रहा है।

टी.बी मुक्त अभियान के अंतर्गत जिले में 01 लाख 48 हजार से अधिक उच्च जोखिम समूह के व्यक्तियों का पंजीयन किया गया है, जिनकी लगातार निगरानी और स्क्रीनिंग की जा रही है। टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के चलते वर्ष 2025 में जिले को 100 दिवसीय अभियान के प्रथम चरण में राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया गया, वहीं वर्ष 2023 में भी निक्षय मित्र अभियान के तहत जिले को सम्मान मिल चुका है। टी.बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर कार्य किए गए हैं। वर्ष 2025 में 118 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, इससे पहले 74 ग्राम पंचायतों को टी.बी मुक्त घोषित किया जा चुका है। इन पंचायतों का चयन विभिन्न स्वास्थ्य मानको जैसे संदिग्ध मरीजों की जांच, टीबी नोटिफिक्शन, सफ्लता दर और पोषण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयनकृके आधार पर किया गया है। कार्यक्रम में टीबी मुक्त रहने वाले 74 ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करते हुए गांधी जी प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, नगरपालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला, उपाध्यक्ष जय प्रकाश मिश्रा, जनपद अध्यक्ष रामकमल सिंह परिहार अपर कलेक्टर जी.एल. यादव, डिप्टी कलेक्टर मायानंद चंद्रा, एवं एनएचएम के डीपीएम गिरीश कुर्रे सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने मोबाईल टी.बी एक्सरे रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

बसना पुलिस की त्वरित कार्यवाही : युवती के अंधे कत्ल का बसना पुलिस ने किया कुछ ही घंटे के भीतर खुलासा

- शादी के वादे से मुकरने और बदनामी के डर से प्रेमी ने ही की थी हत्या, आरोपी प्रेमी लोकनाथ पटेल गिरफ्तार

बसना (समय दर्शन)। महासमुंद जिले के थाना बसना अंतर्गत ग्राम इंद्रपुर में हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में महासमुन्द एस पी के कुशल मार्गदर्शन एवं बसना थाना निरीक्षक शरद दुबे की अगुवाई में पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.03.2026 की सुबह ग्राम इंद्रपुर निवासी रामदास अजगल्ले ने सूचना दी कि उसकी 21 वर्षीय पुत्री पुष्पा अजगल्ले, जो जन्म से मूकबधिर थी, का शव घर से करीब 150 मीटर दूर रविलाल नाग के खेत में लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला है। मृतिका के सिर और चेहरे पर किसी भारी वस्तु से प्राणघातक वार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महासमुंद के निर्देशन विशेष टीम का गठन किया गया। घटनास्थल पर तत्काल वैज्ञानिक अधिकारी (स्र्स्र्) और डॉग स्क्वाड को बुलाकर सूक्ष्म निरीक्षण कराया गया और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (ब्नहस) की धारा 103(1) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।विवेचना के दौरान पुलिस को मृतिका के पिता से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। गांव के ही लोकनाथ पटेल (पिता कीर्तन लाल पटेल, उम्र 27 वर्ष) ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि मृतिका गर्भवती थी और वह लोकनाथ पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। इसी आधार पर पुलिस ने संदेही लोकनाथ पटेल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।आरोपी लोकनाथ पटेल ने पूछताछ में बताया कि पुष्पा के गर्भवती हो जाने के बाद वह उस पर लगातार शादी के लिए दबाव बना रही थी। लोकनाथ समाज में बदनामी के डर से शादी नहीं करना चाहता था और उसने पुष्पा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। दिनांक 23.03.2026 की मध्य रात्रि करीब 12:30 से 01:00 बजे के बीच उसने पुष्पा को बहला-फुसलाकर घर के पीछे खेत में बुलाया। वहां दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद लोकनाथ ने पास पड़े एक भारी पत्थर से पुष्पा के सिर को पटक कर चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम कथन के आधार पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर और घटना के समय पहने हुए खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं, कई आवेदनों का त्वरित निराकरण

शौचालय निर्माण सहित विभिन्न मांगों को मिली स्वीकृति, अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के दिए निर्देश

मुंगेली(समय दर्शन) जिला कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जनदर्शन सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में जिलेभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदनों का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में विकासखंड लोरमी के ग्राम बेड़ापारा निवासी गजेन्द्र पाल द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संबंधित अधिकारी को शौचालय निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। आवेदन की स्वीकृति मिलते ही आवेदक गजेन्द्र पाल ने खुशी जाहिर करते हुए कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया। इसी क्रम में विकासखंड मुंगेली के ग्राम नवलपुर (हड़गांव) निवासी कु. रोशनी ने सहायिका भर्ती प्रक्रिया, लोरमी में अनियमितता, नियमों के उल्लंघन एवं अपात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर आवेदन सौपा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए 04 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। जनदर्शन में ग्राम सिपाही (खैरासेतगंगा) के हजारी लाल साहू ने अपने खेत तक शासकीय रास्ता उपलब्ध कराने, ग्राम जमहा की प्रेमलता सोनवानी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण कराने, ग्राम चकरभाठा की जनपद सदस्य श्रीमती मंदाकिनी हुपेश साहू ने नवागढ़ रोड स्थित लिलवाकापा बायपास चौक में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्पीड ब्रेकर या स्टॉपर लगाए जाने की मांग की। इसके अलावा ग्राम पंचायत छटन के सरपंच लुमेश कुमार सप्रे ने नल-जल योजना के तहत पानी टंकी निर्माण एवं पाइपलाइन विस्तार कार्य कराने, विकासखंड पथरिया के ग्राम भटगांव निवासी भरत लाल ने नया आधार कार्ड बनवाने, विकासखंड लोरमी के ग्राम अमलडीही के देवानंद ने विकलांगता पेंशन स्वीकृत कराने की मांग रखी। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक मामले की जांच कर नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

थाना कोमाखान पुलिस एवं एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्कर पर कार्यवाही

अवैध मादक पदार्थ गांजा की कंटेनर वाहन से तस्करी करते 02 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 12.3003 कि.ग्रा. अवैध मादक पदार्थ गांजा किमती 6 लाख 15 हजार रूपए, कंटेनर वाहन, 02 नग मोबाईल एवं नगदी रकम सहित कुल 26 लाख 20 हजार रुपये की संपत्ति जप्त

वर्ष 2026 में अब तक 57 प्रकरण में 3122.500 किग्रा अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त, कीमत 15 करोड़ 56 लाख 83 हजार

149 आरोपियों मे से 44 छत्तीसगढ़ तथा 105 अन्य राज्यो के आरोपी गिरफ्तार हुए

महासमुन्द (समय दर्शन)। पुलिस अधीक्षक महासमुन्द द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियों को नशीली पदार्थ, अवैध शराब तथा अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के विरूद्ध अभियान चलाने अंतर राज्यीय चेक पोस्ट पर एवं परिवहन के संभावित रास्तों पर मोबाइल

चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की सघन जांच एवं कार्यवाही करने के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 21.03.2026 को हमराह स्टाफह॥ 353 में आने जाने वाले वाहनो की चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक कत्था रंग की कंटेनर वाहन क्रमांक ॥क्र56 ष्ट 2387, जिसमें 02 व्यक्ति सवार होकर अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर उडिसा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे है। सूचक के बताये अनुसार सामने से एक कत्था रंग की कंटेनर वाहन क्रमांक ॥क्र 56 ष्ट 2387 आते दिखा, जिसे रोककर वाहन मे सवार दो व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर कंटेनर चालक ने अपना नाम बाबूलाल पिता ओमप्रकाश उम्र 40 साल निवासी नौगांव नागला भोला मथुरा थाना छाता जिला मथुरा (उत्तरप्रदेश) एवं चालक के बगल में बैठा व्यक्ति रविन्द्र ठाकुर पिता सूजन सिंह उम्र 19 साल निवासी साधन थाना अछनेरा जिला आगरा (उत्तरप्रदेश) बताया।कंटेनर में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में पूछताछ करने पर केबिन में बैंगनी रंग के बैग के अंदर रखे अवैध मादक पदार्थ गांजा को उडीसा राज्य से हरियाणा राज्य में बिक्री करने हेतू लेकर जाना बताये, जिस पर आरोपियों कंटेनर वाहन क्रमांक ॥क्र56 ष्ट 2387 की उपस्थित पुलिस स्टाफ व गवाहों के मौजूदगी मे संदेहियों के कब्जे से एक कत्था रंग की कंटेनर वाहन क्रमांक ॥क्र56 ष्ट 2387 के केबिन में रखे बैंगनी रंग के बैग को संदेहियो से नीचे उतरवाकर तलाशी लेने पर बैग के अंदर 06 पैकेट खाखी रंग के टेप से पैकिंग किया हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा जिसकी मात्रा 12.300 किलोग्राम कीमत 615000 रूपये का, रखे मिला। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही में बाबूलाल से 01 नग मोबाईल, नगदी रकम 1000 रूपये, वाहन क्रमांक ॥क्र56 ष्ट 2387 का आरसी कार्ड एवं संदेही रविन्द्र ठाकुर से एक नग मोबाईल को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 20 (क्च) (द्बद्ब) एनडीपीएस एक्ट का घटित करना पाये जाने से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.03. 2026 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। संपूर्ण कार्यवाही थाना कोमाखान पुलिस व एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की संयुक्त टीम के द्वारा की गयी।

शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगेली में किया गया विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

मुंगेली(समय दर्शन) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमति गिरिजा देवी मेरावी के मार्गदर्शन में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगेली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में महिलाओं को उनके संरक्षण एवं सशक्तिकरण संबंधी कानूनी अधिकार की जानकारी साझा करते हुए घरेलु हिंसा से महिलाओं को संरक्षण कानून, दहेज प्रतिषेध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन, महिला हेल्प लाईन नंबर व अनियमित जीवनशैली और स्वास्थ्य के मुद्दो के बारे में जानकारी देते हुए नियमित मेडिटेशन और व्यायाम करने हेतु जागरूक किया गया तथा शिकायत की प्रक्रिया, संविधान के मूल अधिकार व मूल कर्त्तव्य, नालसा हेल्पलाईन नं. 15100, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध एवं नये कानून की जानकारी दी गई। साथ ही साथ चेक बाउंस, उपभोक्ता फोरम, मोबाईल फोन के लाभ व हानि की जानकारी दी। उक्त शिविर में संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न : कैशलेस चिकित्सा सुविधा की सौगात पर भिलाई में जुटेगा कर्मचारियों का महाकुंभ

- मुख्यमंत्री का होगा भव्य अभिनंदन; छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने कसी कमर

साजा (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित 'कैशलेस चिकित्सा सुविधा' को हरी झंडी दिए जाने के बाद, प्रदेश भर के कर्मचारियों में उत्साह की लहर है। इस ऐतिहासिक निर्णय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आगामी 29 मार्च रविवार को भिलाई के कला मंदिर में एक विशाल 'मुख्यमंत्री अभिनंदन समारोह' का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की मुख्य उद्देश्य: कैशलेस इलाज की सुविधा लागू करने हेतु मुख्यमंत्री जी का आभार एवं भव्य अभिनंदन है।

कर्मचारियों के संघर्ष और अधिकारों की जीत- संघ की प्रदेश अध्यक्षा उषा चंद्राकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लागू होना प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा गंभीर बीमारियों के वक्त आर्थिक तंगहाली एक बड़ा संकट बनकर खड़ी होती थी। अब इस सुविधा से कर्मचारियों को नकद राशि की चिंता से मुक्ति मिलेगी। यह आयोजन केवल एक अभिनंदन समारोह नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों की एकता, उनके लंबे संघर्ष और उनके अधिकारों की जीत का महा-उत्सव है।

प्रदेश भर से जुटेगा जनसैलाब- कार्यक्रम की भव्यता को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बेमेतरा जिला सहित प्रदेश के हर कोने से कर्मचारियों के शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। बेमेतरा से प्रमुख पदाधिकारी दुर्ग सभांगीय सचिव नरेश बघेल, जमुना सिंह राज, लोमन सिंह वर्मा, पवन साहू, बसन्त कौशिक, दीपक राजपूत, अर्जुन वर्मा, किशन ठाकुर, पोखन साहू, कौशल अवस्थी, अजय यादव, सुनील साहू, सुनील राजपूत, गंगाधर दुबे और योगेंद्र साहू ने संयुक्त रूप से अपील की है कि कर्मचारी साथी अधिक से अधिक संख्या में भिलाई पहुँचकर इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनें।

महत्वपूर्ण प्रभाव- नई सुविधा के तहत अनेकों प्रभाव देखने को मिलेगा कर्मचारियों को इलाज के लिए अचानक बड़ी धनराशि जुटाने के मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। प्रदेश के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच मिलेगा। आपातकालीन स्थिति में बिना किसी वित्तीय बाधा के त्वरित उपचार संभव होगा।

संगठन के पदाधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों से कार्यक्रम की गरिमा और अनुशासन बनाए रखने का विशेष आग्रह किया है ताकि मुख्यमंत्री जी का यह अभिनंदन समारोह राज्य के इतिहास में यादगार बन सके।

संक्षिप्त समाचार

मछली वाला बर्फ आम नागरिक खाए यही है विष्णु का न्यू नॉर्मल

बिलासपुर, 24 मार्च 2026। गर्मी आरंभ होते ही जिन दो उत्पादन पर खाद्य विभाग को तुरंत नमूने एकत्र करना चाहिए उनकी और ध्यान नहीं दिया जाता। बर्फ और लोकल आइसक्रीम शहर की पुरानी बस्ती में यह दोनों काम खूब होते हैं। खाद्य और अखाद्य बर्फ के वर्गीकरण का पालन विभाग बिल्कुल नहीं करता, अखाद्य बर्फ गन्ना रस, लस्सी और बर्फ गोला में खूब प्रयोग होता है यही हाल आइसक्रीम और फलूदा का है। लाइसेंस जारी करने के प्रक्रिया इतनी झोल वाली है कि इसके हासिल कर लेने से गारंटी का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। 2025 में भारत में पैकेज फूड और फूड सर्विस का कुल उपयोग 16 लाख करोड रुपए से अधिक रुपए का है और दवाइयां की खपत 3 लाख करोड रुपए की है। 2 करोड़ से ऊपर बिक्री केंद्र हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की संख्या केवल 8000 है। औसतन एक अधिकारी को 2500 दुकान देखनी है। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी ऐसी ही है। स्वीकृत पद से आधे ही भरे हुए हैं। Fasai से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला सिर्फ 200 हैं और भारत में जिलों की संख्या 800 है। कस्बे 5000 यदि सैंपल ले भी लिया जाए और जांच से भाग जाए तो न्यायालय में रिपोर्ट टिकती नहीं है। इस विभाग के बजट की क्या बात करें 620 करोड़ का बजट था 520 करोड़ में निपटा दिया और 2025-26 में भी 525 करोड़ दिए। भारत की जनसंख्या अमेरिका से चार गुना है और यह खाद्य जांच पर बजट का 0.2% खर्च करते हैं और भारत 0.02% खर्च करता है। ऐसे भी यदि मछली बेचने वाले बर्फ को आम नागरिकों के बीच बचा जाए तो इस देश का न्यू नॉर्मल ही माना जाएगा।

उल्लास महापरीक्षा में दिखा शिक्षा का उत्साह, बंदियों और पुर्नवासितों ने भी थामी कलम

जगदलपुर। बस्तर जिले में शिक्षा और ज्ञान की नई अलख जगाने के उद्देश्य से आयोजित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को महापरीक्षा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। जिला प्रशासन की इस अनूठी पहल ने पूरे जिले को साक्षरता के महापर्व में सराबोर कर दिया, जहाँ सुदूर वनांचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक शिक्षा का उत्साह देखने को मिला। कलेक्टर आकाश छिकारा और जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित इस परीक्षा में जिले भर के कुल 25,706 परीक्षार्थियों ने सम्मिलित होकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। यह आयोजन महज एक परीक्षा नहीं, बल्कि उन बुजुर्गों और युवाओं के लिए स्वावलंबन की एक नई शुरुआत बनकर उभरा है, जो किन्हीं कारणों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे।

इस महापरीक्षा की सबसे प्रेरक और हृदयस्पर्शी तस्वीर जगदलपुर के केंद्रीय कारागार और पुनर्वास केंद्रों से निकलकर सामने आई। जहाँ एक ओर जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले 94 पुरुष और 47 महिला बंदियों ने साक्षरता की मुख्यधारा से जुड़कर अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर आड़ावाल स्थित पुनर्वास केंद्र में 28 पुर्नवासितों ने भी हाथों में कलम थामकर विकास और शांति की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। इन नव-साक्षरों का उत्साह यह बताने के लिए काफी था कि बस्तर अब पूर्ण साक्षर होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है और ज्ञान का उल्लास हर वर्ग के जीवन में रोशनी फैला रहा है। उल्लास परीक्षा के लिए जिले भर में 812 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे, ताकि घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभागियों को भी परीक्षा देने में कोई असुविधा न हो। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों की पढ़ने, लिखने और बुनियादी अंक गणित की क्षमता को बारीकी से परखा गया। इस दौरान संयुक्त संचालक एचआर सोम ने केंद्रीय जेल का सघन निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। उनके साथ जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल, नोडल अधिकारी राकेश खापर्डे और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिक्षा के इस उत्सव में सामुदायिक भागीदारी भी देखते ही बनी। विकासखंड बस्तर के ग्राम बालेंगा को मॉडल उल्लास केंद्र के रूप में सजाया गया था, जहाँ उल्लास सेल्फी जोन विशेष रूप से ग्रामीणों के आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी भारती देवांगन और संकुल समन्वयकों की उपस्थिति में ग्रामीणों ने बड़े ही उत्साह के साथ परीक्षा दी। इसी तरह लोहंडीगुड़ा के चित्रकोट केंद्र में भी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी उमड़े। कलेक्टर आकाश छिकारा ने इस सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जब जिले का हर नागरिक बुनियादी साक्षरता प्राप्त कर लेगा, तभी बस्तर सही मायने में सशक्त बनेगा। सफल उम्मीदवारों को जल्द ही बुनियादी साक्षरता का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा।

जिला पंचायत सीईओ ने ली समय-सीमा की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

महासमुन्द (समय दर्शन)। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला पंचायत सीईओ श्री नंदनवार ने बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप सभी विभागों को समय सीमा के अंतर्गत सभी लंबित बिलों को इस माह की 25 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने धान उठाव की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में धान उठाव के कार्य में तेजी लाएं और शेष धान का उठाव शीघ्र करें। खाद्य अधिकारी ने बताया गया कि अभी तक 9.40 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। श्री नंदनवार ने जिले में कुपोषण को समाप्त करने के लिए अधिकारियों को चिन्हांकित कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उन्हें पोषित करने की जिम्मेदारी दी है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पीएम श्री स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने तथा स्कूल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की सतत निगरानी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। वहीं सभी स्कूलों में बालिका शौचालयों को सुचारू रूप से संचालित रखने के निर्देश भी दिए गए। सीईओ श्री नंदनवार ने जनगणना से संबंधित तैयारियों पर निर्देश देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जानकारी अद्यतन रखने और निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने कहा है। साथ ही प्रशिक्षण एवं एंट्री कार्यों को भी तेजी से पूर्ण करने के लिए कहा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि विभाग को शत-प्रतिशत पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उद्यानिकी विभाग की समीक्षा में लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व पखवाड़ा का आयोजन कर लोगों को उनके राजस्व अधिकारों के प्रति जागरूक, दस्तावेजों का सत्यापन तथा मौके पर ही समस्याओं का समाधान करें। प्राप्त आवेदनों एवं निराकृत प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार एवं अन्य लंबित राजस्व प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों, लोक सेवा गारंटी की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य विभागों से संबंधित पत्रों एवं लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने जनदर्शन में संवेदनशीलता से सुनी नागरिकों की समस्याएं

जनदर्शन में आज कुल 74 आवेदन हुए प्राप्त

जांजगीर-चांपा //समय दर्शन // कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलता से सुनी। कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। जनदर्शन में कुल 74 आवेदन प्राप्त हुए है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आवेदनों पर संज्ञान लेते हुए जनदर्शन के दौरान ही तत्काल संबंधित अधिकारी से दूरभाष पर चर्चा की और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

जनदर्शन में तहसील मुख्यालय जांजगीर निवासी श्री पवन राठौर द्वारा भूमि सीमांकन करवाने, तहसील पामगढ़ के ग्राम रहौद निवासी श्रीमती उषा देवी द्वारा राशन कार्ड में खाद्य आबंटन संबंधी समस्या दूर करने, तहसील चाम्पा के ग्राम कोसमन्दा निवासी श्री रोहित कुमार राशनकार्ड जारी करवाने, विकासखंड अकलतरा के ग्राम हरदी निवासी श्रीमती शांतिबाई साहू द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ दिलवाने, जांजगीर के श्रीमती सुनीता राठौर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार अन्य आवेदकों द्वारा पीएम आवास, सीमांकन, बंटाकन, त्रुटि सुधार, राशन कार्ड, आधार कार्ड सुधार, पेंशन, राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने सहित विभिन्न विषयों पर आवेदन प्रस्तुत किये गये।

विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का हुआ जिला स्तरीय शुभारंभ

टी.बी. मुक्त पंचायतों एवं मेधावी छात्राओं को किया गया सम्मानित

जांजगीर-चांपा//, समय दर्शन //विश्व क्षय दिवस के अवसर पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय शुभारंभ 24 मार्च से जिला ऑडिटोरियम, जांजगीर में किया गया। इसके साथ ही टीबी मुक्त पंचायतों एवं मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीबी उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य को गति देना है। इस दौरान टीबी मुक्त पंचायतों को सम्मानित किया गया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे, जिला पंचायत सदस्य श्री राजकुमार साहू, जिला पंचायत सदस्य श्री लोकेश साहू, श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, श्री प्रदीप पाटले, सीएमएचओ डॉ अनिता श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल, डीपीएम श्री उत्कर्ष तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि टीबी पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी है, इसके लिए समय पर जांच और नियमित इलाज बेहद जरूरी है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि टीबी के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं और उपचार पूरा करें। उन्होंने क्षय रोग के विरूद्ध विशेष जागरूकता चलाने एवं स्वयं के द्वारा भी किट प्रदान करने एवं ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुचाने कहा। सीएमएचओ ने बताया कि जिले में टीबी उन्मूलन के लिए 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर-घर सर्वे, स्क्रीनिंग और उपचार की व्यवस्था किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी टीबी मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया और जनजागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इसके साथ ही टी.बी. मुक्त पंचायतों एवं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना अंतर्गत सत्र 2024-25 में जिले की मेधावी छात्रा कु. खुशी देवांगन, कु. ज्योति ओग्रे, कु. ईशा, कु. अदिति देवांगन, कु. रोशनी जोगी, कु. पुष्पा चौहान को पुरस्कार प्रदान किया गया।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में थाना चांपा पुलिस की सख्त कार्यवाही, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध धारा 298 BNS के तहत कार्रवाई का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

जांजगीर //समय दर्शन //प्रार्थी योगेश कुमार देवांगन निवासी भोजपुर, थाना चांपा ने 15 मार्च 2026 को थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आयोजित भागवत कथा के अवसर पर भोजपुर स्थित समलाई मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने मुख्य मार्ग किनारे एक फ्लेक्स बैनर लगाया गया था।

घटना के दिन, कलश यात्रा के दौरान जब श्रद्धालु हसदेव नदी से जल भरकर लौट रहे थे, उसी समय आरोपी राजेश वाल्टर ने उक्त फ्लेक्स बैनर को फाड़ दिया, जिससे हिन्दू धर्म की आस्था को ठेस पहुंची।

रिपोर्ट के आधार पर* थाना चांपा में अपराध क्रमांक 111/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान आरोपी राजेश वाल्टर (71 वर्ष), निवासी मिशन फाटक रोड, भोजपुर चांपा ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया।इस कार्रवाई* में थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक वैष्णव, सहायक उप निरीक्षक बाबूलाल दिवाकर एवं थाना चांपा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

संभव नहीं दिखता छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन का चुनाव

रायपुर/बिलासपुर, 24 मार्च 2026। 27 मार्च को होने वाला छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन पर फिर से संकट के बादल छा गए हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद ही कक्ष क्रमांक 5 में आपत्तियों का ताता लग गया है। पहले ही दिन व्हिसल ब्लोअर यशराज सिंह और बिनु बैनेट की ओर से 15 शपथ पत्र के साथ आपत्तियों की गई, पूर्व वाइस चेयरमैन अतुल ऑथर ने 20 आपत्तियां प्रस्तुत की है। लॉरेंस गुट से भी कुछ आपत्तियां आई है। ऐसा लगता है कि 2022 की कालातीत मतदाता सूची और 2024 की निरस्त मतदाता सूची का भेद खुल जाने के बाद अब इस चुनाव पर संकट छा गया है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद 17 तारीख से 20 तारीख तक दाबा आपत्ति आमंत्रित की गई जबकि दावा आपत्ति मतदाता प्रकाशन सूची के बाद आमंत्रित होनी चाहिए।

समिति चुनाव धारा 33(1) रहती है कि मतदाता सूची में कोई भी नया नाम नहीं जोड़ा जा सकता। 2022 की मतदाता सूची कालातीत है और 2024 की मतदाता सूची को विधि मान्य नहीं पाया गया। नहीं मतदाता सूची 2027 में ही बने सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ डायोसिस बोर्ड ऑफ़ एजूकेशन का चुनाव होना दिखाई नहीं देता।

इतनी कानूनी पेचीदगियों के बाद चुनाव अधिकारी एसडीएम रायपुर चुनाव कराने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं।

अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य: पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल

भाजपा कार्यकर्ताओं के वैचारिक सशक्तिकरण के लिए पिरदा में मंडल प्रशिक्षण वर्ग का भव्य आयोजन,विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को दिया 'अंत्योदय' का मंत्र

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल पिरदा में फूंका चुनावी बिगुल, कहा- प्रशिक्षण ही कार्यकर्ता की असली शक्ति है

बसना (समय दर्शन)। भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पिरदा के समरसता भवन में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान मंडल प्रशिक्षण वर्ग' का गरिमामय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसना विधायक डॉ. संपत अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा-अर्चना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि और संगठन के ध्वजारोहण के साथ हुआ।

विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बौद्धिक और वैचारिक विकास की पाठशाला है। प्रशिक्षण ही वह माध्यम है जिससे एक सामान्य कार्यकर्ता कुशल नेतृत्वकर्ता बनकर उभरता है।

विधायक डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और हमारी ताकत हमारी विचारधारा है। हमें गर्व है कि हम उस संगठन के सिपाही हैं जिसका मूल मंत्र 'अंत्योदय' है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उदय ही हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझने और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लेना है।

अपने उद्बोधन के अंतिम चरण में विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद हमें सिखाता है कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण होना चाहिए। आज के समय में जब राजनीति के मायने बदल रहे हैं, तब भाजपा का कार्यकर्ता अपने सेवा भाव और संस्कारों से समाज में एक मिसाल पेश कर रहा है। आने वाले समय में यह प्रशिक्षण वर्ग हमारे मंडल स्तर की कार्यक्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष हरप्रसाद पटेल,जिला महामंत्री जितेन्द्र त्रिपाठी, जिला मीडिया प्रभारी नवीन साव, गढफुलझर मण्डल पूर्व अध्यक्ष माधव साव,भाजपा मण्डल पिरदा अध्यक्ष अभिमन्यु प्रधान, सोहन पटेल, हेमलाल सिदार, भाजपा पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी और बड़ी संख्या में निष्ठावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरी ऊर्जा के साथ प्रशिक्षण में भाग लिया।

खबर-खास

श्री श्री विश्वविद्यालय में शहद से स्वरोजगार तक का नया मार्ग

कटक/रायपुर (समय दर्शन)। ओडिशा के कटकस्थित श्री श्री विश्वविद्यालय में मूल्य वर्धित मधुमक्खी उत्पादों पर एक क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को पारंपरिक शहद उत्पादन से आगे बढ़कर आय के नए स्त्रोत विकसित करने के लिए प्रशिक्षित करना था। यह आयोजन 'फेस्टिवल ऑफइंस्पिरेशन' के तहत किया गया, जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूर्ण होने तथा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन कृषि संकाय की सहायक प्राध्यापिका एवं प्रशिक्षण समन्वयक डॉ. सीमा त्रिपाठी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने प्रतिभागियों को शहद आधारित नवाचारी उत्पादों के निर्माण और विपणन से जुड़ी व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी। इस प्रशिक्षण में ओडिशा के कटक, खौर्द्धा, ढेंकानाल, मयूरभंज, जगतसिंहपुर और क्योंझर जैसे जिलों से आए मधुमक्खी पालकों और किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी ने मधुमक्खी पालन में मूल्य संवर्धन और उद्यमिता के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाया। कृषि संकायाध्यक्ष प्रो. (डॉ.) एस. कुमारस्वामी ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थानों और किसानों के बीच सहयोग से नवाचार, स्थिरता और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिल सकता है। कार्यक्रम को डॉ. शुभ्रज्योति पंडा का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छात्रों और शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए मूल्य वर्धित उत्पादों का प्रदर्शन रहा। इनमें हनी ओट्स लड्डू, बीज़वैक्स लिप बाम, हनी साबुन, हनी चिक्की, हनी से भरी चॉकलेट्स और हनी मफिंस शामिल थे। इन उत्पादों ने न केवल पोषण के दृष्टिकोण से महत्व को दर्शाया, बल्कि बाजार में उनकी संभावनाओं को भी रेखांकित किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नवाचारी और बाजार-उन्मुख उत्पादों के माध्यम से आय के स्त्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, मधुमक्खियों की परागण, जैव विविधता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया तथा वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन अपनाने पर जोर दिया गया। कुलपति प्रो. डॉ. तेजप्रताप एवं कार्मिक निदेशक स्वामी सत्यचैतन्य ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजकों की सराहना की।

महानदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर की गई कड़ी कार्रवाई, एक चैन माउंटेन मषीन और एक हाईवा जब्त

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा तहसील राजिम अंतर्गत ग्राम हथखोज स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार,19 मार्च 2026 को टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान क्षेत्र में अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर विभाग ने एक चैन माउंटेन मशीन को लावारिस स्थिति में जब्त कर मौके पर ही सीलबंद कर दिया। इसके साथ ही एक हाईवा वाहन को भी जब्त कर सुरक्षा के लिए थाना राजिम की अभिरक्षा में रखा गया है।

अधूरे निर्माणाधीन भवन में चल रहा नर्सिंग कॉलेज, सरकारी दिशा निर्देशों कि उड़ी धज्जिया

हथेली से बोर का पानी पीने को मजबूर छात्र, खुले बिजली तार से हर पल खतरा – जिम्मेदारों की चुप्पी

गरियाबंद (समय दर्शन)। क्षेत्र में संचालित एक नर्सिंग कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार सामने आया है।अधूरे निर्माणाधीन भवन में पढ़ाई संचालन,पीने के पानी की समुचित व्यवस्था का अभाव और खुले बिजली तारों के बीच छात्रों को शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस संस्थान का कोई उच्च स्तरीय निरीक्षण भी नहीं हुआ है, जिससे जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार कोदोबतर में संचालित नर्सिंग कॉलेज का भवन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ यंहा अभी तक निर्माण कार्य चल रहा है,बावजूद इसके वहां नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।भवन अधूरा होने के कारण न तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं और न ही छात्रों के बैठने के कमरे में पर्याप्त पंखा की व्यवस्था है। खुले शौचालय बाहर से एक गेट के सहारे चल रहे है। अग्नि सेफ्टी भी नदारत दिखी सबसे गंभीर स्थिति पीने के पानी को लेकर है। कॉलेज परिसर में स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्र-छात्राएं बोरवेल से सीधे पानी को हथेली में लेकर पीने को मजबूर हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।वहीं,परिसर में खुले बिजली के तार लटक रहे हैं जिसके नजदीक मजूदर कार्य कर रहे है वही नजदीक से बच्चे भी गुजर रहे है जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।छात्रों और स्टाफ के लिए यह स्थिति लगातार खतरा बनी हुई है। विगत पांच माह से अधिक समय से आधे अधूरे मकान मे किन नियमों के तहत चल रहे है यह वंहा के प्राचार्य तक नहीं बता पाए।

राज्य शासन भी कुंभकरणी निद्रा मे : सैकड़ो के तादाद मे प्रदेश भर से इस नर्सिंग कॉलेज मे बच्चे पढ़ने आते है। निर्माणाधीन भवन मे हमेशा हादसे कि आशंका बनी रहती है। कोई अप्रिय हादशा होने के बाद ही क्यू प्रशासन जगता है ? विभागीय भ्रष्टाचार का खामियाजा बच्चो को भुगतना न पड जाय। नियमों के अनुसार नर्सिंग कॉलेजों को Indian Nursing Council (INC) के मानकों का पालन करना अनिवार्य है,जिसमें सुरक्षित भवन,स्वच्छ पेयजल,बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं आवश्यक होती हैं।लेकिन यहां इन मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है।

निरीक्षण नहीं,जिम्मेदार बेखबर: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इस कॉलेज का किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है।इससे प्रशासनिक लापरवाही साफ झलकती है और सवाल उठता है कि आखिर किसकी शह पर यह सब चल रहा है।

मांग और चेतावनी: अधूरे भवन,असुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में संचालित यह नर्सिंग कॉलेज न केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि उनकी जान को भी जोखिम में डाल रहा है।अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेता है।

इस सम्बन्ध मे इस नर्सिंग कॉलेज के संचालिका से फ़ोन से उनका पक्ष जानने फ़ोन लगाया गया किन्तु उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया।

टी.बी. मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ

कलेक्टर श्री उइके ने दिखाई हरी झंडी

गरियाबंद (विश्व परिवार)। विश्व क्षय दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय गरियाबंद में टी.बी. मुक्त भारत अभियान के 100 दिवसीय द्वितीय चरण का शुभारंभ संयुक्त जिला कार्यालय के परिसर से किया गया।इस दौरान कलेक्टर बीएस उइके उईके ने अभियान का विधिवत उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं शिवम् नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई प्रचार रैली और सर्वे दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने टी.बी. मुक्त भारत के लिए शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि 24 मार्च से प्रारंभ यह अभियान टी.बी. उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत मितानिन और स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर उच्च जोखिम समूहों एवं टी.बी. के संभावित मरीजों की पहचान करेंगे तथा उनकी जांच और उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उमाशंकर नवरत्न ने बताया कि अभियान के प्रारंभिक 15 दिनों में पूर्व में आयोजित निक्षय निरामय अभियान से छूटे हुए उच्च जोखिम समूह के व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद सभी की एक्स-रे जांच कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर लोगों को जांच एवं उपचार की सुविधा दी जाएगी।अभियान के दौरान जेल,खदान,क्रशर,ईंट भट्ठा,उद्योग और राइस मिल जैसे क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का भी चिन्हांकन कर उनकी जांच और उपचार किया जाएगा।इस व्यापक अभियान में विभिन्न शासकीय विभागों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।कार्यक्रम के अंत में जिला चिकित्सालय परिसर में शिवम नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ संगोष्ठी एवं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला क्षय अधिकारी डॉ.ए.के.हुमने ने टी.बी. के लक्षण,जांच,उपचार और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी।कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ.वाय.के.ध्रुव,जिला क्षय अधिकारी डॉ.अमन कुमार हुमने,डीएचओ डॉ.लक्ष्मीकांत जांगड़े, चिकित्सा अधिकारी डॉ.एस.के. रेड्डी, डीपीएम गनपत नायक सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यकर्ताओं को दक्ष, प्रवीण बनाना प्रशिक्षण का उद्देश्य -किरण सिंह देव

जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से अपने कार्यकर्ताओं को तराशने, निखारने, प्रवीण व मुखर बनाने के उद्देश्य से निरंतर प्रशिक्षण कार्यशाला लगा रही है। जिसमें संगठन के शीर्षस्थ पदाधिकारी सम्मिलित होकर कार्यकर्ताओं को भाजपा के नीति, सिद्धांत, कार्य पद्धति व जनसेवा कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। आज सोमवार को ग्राम आसना में आयोजित सरगीपाल व बकावण्ड मण्डल की प्रशिक्षण कार्यशाला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष रूप से सात प्रमुख विषयों का चयन किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता हमेशा कर्मष्ठ, निष्ठावान व परिश्रमी होते हैं। प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से उन्हें और दक्ष व प्रवीण बनाना उद्देश्य है, जिससे वे समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और भाजपा की नीतियों को प्रभारी ढंग से पहुंचा सके।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया ने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ता ही भाजपा की पूंजी है। प्रशिक्षण वर्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भाजपा जिलाअध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय ने भी संबोधन दिया। कार्यशाला का संचालन सरगीपाल मण्डल महामंत्री संतोष बिसाई ने किया। कार्यशाला में प्रमुख रूप से सांसद महेश कश्यप, बेवरेज कार्पोरेशन अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ,डा सुभाऊ कश्यप, शेष नारायण तिवारी,प्रदेश प्रवक्ता टेकेश्वर जैन, श्रीनिवास मिश्रा, खेमसिंह देवांगन, रामाश्रय सिंह, रजनीश पाणिग्रही,परीस बेसरा,आर्येंद्र आर्य, नरसिंह राव, ललिता बघेल, प्रदीप देवांगन, सुब्रतो विश्वास, फूलसिंह सेठिया, रोहित त्रिवेदी, प्रकाश झा, अविनाश श्रीवास्तव, अभिलाष यादव, माहेश्वरी ठाकुर , पीताम्बर कश्यप आदि सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे भाजपा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल- भारतीय जनता पार्टी द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अन्तर्गत समूचे देश में प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं।

डेल्टा एक्सचेंज को मिल रही जबरदस्त भागीदारी, 6 अरब डॉलर प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर क्रिप्टो एफएंडओ वॉल्यूम

रायपुर : भारत के नंबर 1 क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस (एफएंड ओ) एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज ने फरवरी 2026 तक औसतन 6 अरब डॉलर का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया है, जो देश में क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की तेजी से बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है। इस वृद्धि को रायपुर जैसे उभरते ट्रेडिंग हब से भी मजबूती मिल रही है, जहां वित्तीय बाजारों में भागीदारी अब पारंपरिक निवेश साधनों से आगे बढ़ रही है। रायपुर में रिटेल निवेशकों की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। इक्विटी और ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ-साथ अब क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में भी रुचि दिखाई देने लगी है। ट्रेडर्स मेला जैसे आयोजन इस बदलाव को गति दे रहे हैं, जहां ट्रेडर्स, शिक्षकों और प्लेटफॉर्म्स को एक साथ लाकर उन्नत ट्रेडिंग उपकरणों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। डेल्टा एक्सचेंज ट्रेडर्स को बिना क्रिप्टो खरीदे ही क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग की सुविधा देता है। सभी कॉन्ट्रैक्ट्स रूपये में सेटल होते हैं और केवल रूपये में ही जमा स्वीकार किया जाता है, जिसे भारतीय बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है। यह व्यवस्था रायपुर जैसे उभरते बाजारों के लिए खासतौर पर उपयोगी है, जहां निवेशक पारदर्शिता, सरलता और पूंजी दक्षता को प्राथमिकता देते हैं। कम मार्जिन की आवश्यकता भी रिटेल ट्रेडर्स के लिए इसे अधिक सुलभ बनाती है। डेल्टा एक्सचेंज ने हाल ही में एल्गो मार्केटप्लेस लॉन्च किया है, जो विशेषज्ञों द्वारा तैयार नियम-आधारित रणनीतियों के जरिए क्रिप्टो ट्रेडिंग में भाग लेने का नया तरीका प्रदान करता है। उपयोगकर्ता इन रणनीतियों को देख सकते हैं, उनके प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में सब्सक्राइब कर सकते हैं और रणनीति को उनकी जगह पर ट्रेड करने दे सकते हैं।

ट्रेड डील-अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन

दुर्ग। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के विरोध में देश के किसान संगठनों ने आज अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद के खिलाफप्रदर्शन किया, देश के किसान संगठनों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने भी दुर्ग में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक एड राजकुमार गुप्त ने कहा कि आज के दिन ही साम्राज्यवादी हुकूमत के खिलाफ देश की आजादी के लिए संघर्षरत शहीद भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आज किसानों को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा है, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था जवाबी हमलों के बाद खाड़ी में 22 दिन से युद्ध चल रहा है जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। खेती किसानी के सभी उपकरण डीजल से चलते हैं और डीजल नहीं आ रहा है इसके अलावा खाद के बिना किसानी करना संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष आई के वर्मा ने कहा कि ट्रेड डील के अनुसार अमेरिका से मक्का, सोयाबीन, कपास, दलहन दूध और डेयरी उत्पादों के शून्य शुल्क में आयात होने के कारण उत्पादक किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। किसानों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष उत्तम चंद्राकर ने भगतसिंह और गांधी जी का स्मरण करते हुए कहा कि जिस तरह गांधी जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी, नमक सत्याग्रह किया था वैसे ही किसानों को साम्राज्यवाद की लूट के खिलाफ संघर्ष करना होगा।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

प्र0क्र0 202602100600015 अ-2 वर्ष 2025-26

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका वेद प्रकाश पिता/पति सुरेश कुमार वर्मा, निवासी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा ग्राम-अखरा, प.ह.न. 35, तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 44/34 रकबा 0.0135 है., भूमि पर आवासीय प्रयोजन में डायवर्सन कराने हेतु डायवर्सन किये जाने के लिये आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 के तहत प्रस्तुत किया है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 30/03/2026 न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23/03/26 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.)

जिले में पर्यटन विकास को मिलेगी गति

जिले में नवीन पर्यटन स्थलों के सुविधाओं को लेकर की गई समीक्षा

गरियाबंद (विश्व परिवार)। कलेक्टर बीएस उइके ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय पर्यटन समिति की बैठक ली।इस दौरान जिले में नवीन पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की।इस अवसर पर सीतानदी-उदंती टाईगर रिजर्व के उप निदेशक वरूण जैन,जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चंद्राकर डीएसपी सुश्री निशा सिन्हा,डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा भेड़िया, अंत्यवसायी के कार्यपालन अधिकारी सुश्री रश्मि गुप्ता सहित अन्य अधिकारी एवं पर्यटन समिति के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में गरियाबंद जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों, संभावित पर्यटन स्थलों तथा पर्यटन सुविधाओं के विकास को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर जिले में अपार संभावनाएं है। इसके लिए हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होगी। बैठक में तौरेंगा जलाशय में नौकायान एवं नौकाविहार संचालन की अनुमति के विषय पर कहा गया है कि तौरेंगा क्षेत्र के आसपास पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। ताकि पर्यटक यहॉ असानी से आ सके।इसके लिए संबंधित विभागों को सुरक्षा मानकों,लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित चालक तथा दुर्घटना रोकथाम उपायों को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि सही दिशा में काम होने पर यह स्थान जिले का प्रमुख आकर्षण बन सकता है।

दूसरे चरण में जिले में नवीन पर्यटन स्थलों के चिन्हांकन पर विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों ने संभावित स्थलों की सूची प्रस्तुत की,जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य,सांस्कृतिक महत्व और पहुंच सुगमता के आधार पर प्राथमिकता तय की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्थल का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अंतर्गत निजी होटलों के पंजीयन की प्रगति पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन से पर्यटन सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, जिससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा।उन्होंने होमस्टे नीति 2025-30 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने सिकासेर, भाठीगढ़,आमामोरा को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजने को कहा।

कलेक्टर ने जिले में संचालित निजी होटलों, लॉज, रिसॉर्ट, होमस्टे एवं अन्य आवासीय ईकाईयों का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के साथ पंजीयन कराने को कहा।उन्होंने जिले के प्राइवेट होटलों का रजिस्ट्रेशन ऑन छत्तसीगढ़ टुरिज्म बोर्ड के तहत् जिले में संचालित सभी निजी होटल/आवासीय ईकाईयों का पंजीयन की ऑनलाईन एवं ऑफ्लाईन दोनों के माध्यम से कराने को कहा।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बालोद (छ.ग.)

निविदा क्र. 04/ले.शा./ का.अ. /लो.स्वा.यां.खण्ड/ 2026 — बालोद, दिनांक : 18-03-2026

निविदा आमंत्रण सूचना (मैनुअल पद्धति)

मैनुअल निविदाएं प्रपत्र-ए में प्रतिशत दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद द्वारा के एकीकृत पंजीयन व्यवस्था ई-रजिस्ट्रेशन कीं सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण-

नि.सू.क्रं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
04	बालोद जिले के उद्यानिकी विभाग में पाईप लाईन बिछाने तथा अन्य कार्य (शेड्यूल के अनुसार संपूर्ण कार्य सामग्री सहित)	रू. 11.17 लाख

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि :- 06-04-2026 समय सायं 05:30 बजे तक

निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि :- 10-04-2026 समय सायं 05:00 बजे तक

स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि :- 16-04-2026 समय सायं 05:30 बजे तक

उपरोक्त कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी दिनांक 18/03/2026 से एवं कार्यालयीन समय पर कार्यालय में देखे जा सकते है ।

G-252607325/2

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालोद
जिला-बालोद (छ0ग0)

स्वामित्वधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक रोहित खड़तकर द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स ग्राम छाटा, पोस्ट देवादा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.) 491111 से मुद्रित कर मकान नं.-107, वार्ड नं. 26, मदर टेरेसा वार्ड, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.)- 494001 से प्रकाशित। संपादक :- रोहित खड़तकर, मो. 9827104452, दुर्ग कार्यालय- फोन नं.-0788-4051213, रायपुर कार्यालयः-0771-4218364, ईमेल - samay.darshan191@gmail.com पं. क्र. CTHIN/26/A1375

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

25 मार्च 2026

दोपहर 12:00 बजे

4.95 लाख से अधिक हितग्राहियों के बैंक खाते में

₹495.96 करोड़

आदान राशि वितरण कार्यक्रम

पं. चक्रपाणि शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान, बलौदाबाजार
जिला: बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

बजट 2026-27 में **₹600 करोड़** का प्रावधान

भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जा रही **₹10,000 प्रति वर्ष** की आर्थिक सहायता

वर्ष 2025 में **5.62 लाख** से अधिक हितग्राहियों के खातों में **₹562.11 करोड़** से अधिक की राशि अंतरित

22,028 बैगा-गुनिया परिवारों को भी मिल रहा लाभ

साय सरकार में मेहनतकश हाथों को मिल रहा संबल, सुरक्षा और सम्मान

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in